प्रकाशन का गौरवाशाली 14वाँ वर्ष

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

वर्ष 14 | अंक 46 | मूल्य 15 रुपये | 06-12 अप्रैल, 2025

सेवा, सुशासन के 3 वर्ष

देश में छाए पुष्कर सिंह धामी

मोदी सरकार का वक्फ बोर्ड पर "कंट्रोल"

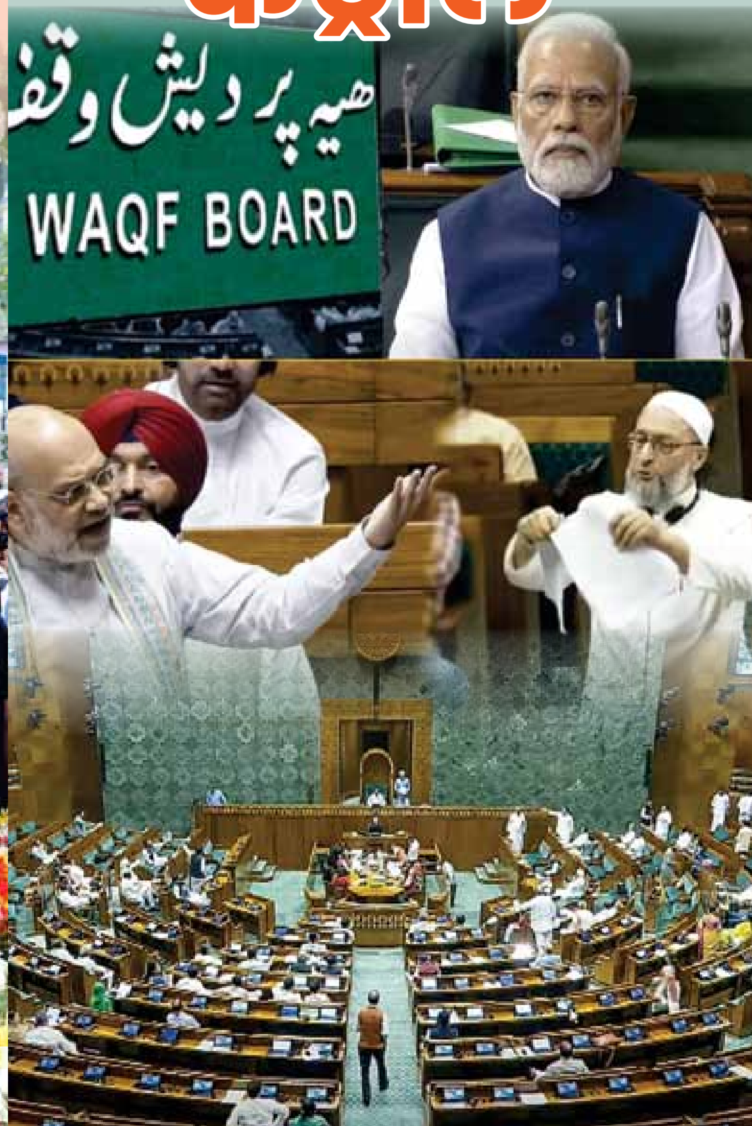

वर्ष 14 | अंक 46

दिव्य हिमगिरि

06-12 अप्रैल, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

ब्यूरो प्रमुख
मोनिका डबराल

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार : डॉ. रजनीश गौतम
पौडी : रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार : के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर : हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली : मुकेश रावत
रुड़की : श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल : शीतल तिवारी
अल्मोड़ा : संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर : अजय शर्मा
प्रसार : रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित। संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

विश्व में व्यापार युद्ध का मंडराता खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत सहित दुनिया के कई देशों को शुल्क युद्ध में घसीट लिया है। उन्होंने जवाबी शुल्क की घोषणा कर एक तरह से टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। अमेरिका की ओर से भारी शुल्क थोपे जाने से स्वाभाविक रूप से अब विश्व में व्यापारिक परिदृश्य बदलेगा और इससे व्यापार युद्ध की आशंका सच साबित हो सकती है। अगर भारत पर इसका प्रभाव पड़ा, तो अमेरिका भी दूसरे देशों के जवाबी शुल्क से नहीं बच सकेगा। दरअसल, राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत में अमेरिका के सामान पर लगने वाले अधिक शुल्क का सवाल बार-बार उठाते रहे हैं। उन्होंने इसे विवाद का मुद्दा भी बनाया। मगर अब अमेरिका ने भारत पर छब्बीस फीसद शुल्क लगा कर साफ कर दिया है कि वह इस विवाद को शायद आगे ले जाना चाहता है। स्पष्ट है कि अब दोनों देशों के परस्पर निर्यात पर दूरगामी असर पड़ेगा। वहीं भारत के साथ अमेरिका के व्यापार संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ना भी तय लग रहा है। ऐसे में भारत यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई देशों से व्यापार के विकल्प पर विचार कर सकता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भारत ने अमेरिका को 78 अरब डॉलर का निर्यात किया था जो कुल निर्यात का अठारह फीसद ही है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता लघु और मझोले उद्यमों के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव की है। कृषि उत्पादों, औषधियों और मशीनरी पर असर पड़ने की आशंका जताई जा चुकी है। निवेशकों के छिटकने और निर्यात में गिरावट के बावजूद भारत इस झटके को सहने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वह सिर्फ अमेरिकी बाजार पर ही निर्भर नहीं। भारत अब अन्य निर्यात बाजारों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। अगर अमेरिका को अपनी कंपनियों के हितों की चिंता है, तो भारत के लिए भी यह स्वाभाविक है। ऐसे में जरूरी है कि दोनों देश बीच का कोई रास्ता निकालें। ऐसा न होने पर दोनों ओर से निर्यात घटेगा और शुल्क में बढ़ोतरी की वजह से अमेरिकी बाजार में कई चीजें महंगी हो जाएंगी। ट्रंप विश्व व्यापार में एक नई व्यवस्था कायम करने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि इससे वे अमेरिका की आर्थिक बुनियाद को कमजोर ही करेंगे। भारत से व्यापार संबंध बिगाड़ कर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। यही नहीं अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ के मुद्दे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की ओर से चीनी सामानों पर शुल्क लगाए जाने के बाद बीजिंग ने भी जवाबी टैरिफ का ऐलान कर दिया है। चीन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में अमेरिकी सामानों पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और चीन को चेतावनी दी है। इसे दुनिया की इन दो बड़ी आर्थिक ताकतों के बीच ट्रेड वॉर तेज होने का संकेत माना जा रहा है। भारत पहले से ही इस टैरिफ विवाद में फंस चुका है। इधर बीजिंग ने कहा कि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नुकसान हुआ है. इसी वजह से वह पारस्परिकता का हवाला देकर अपने व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ बढ़ाने का बहाना बना रहा है। बीजिंग ने यह भी कहा कि अमेरिका का यह रवैया उन लाभों को नजरअंदाज करता है, जो वर्षों की व्यापार वार्ताओं के जरिए सभी देशों को मिले हैं।

कुँवर राज अस्थाना

सेवा, सुशासन के 3 वर्ष देश में छाए पुष्कर सिंह धामी

तीन साल के जश्न में पीएम मोदी ने सीएम धामी को '2027' का भी दिया बधाई संदेश

कुँवर राज अस्थाना
संपादक

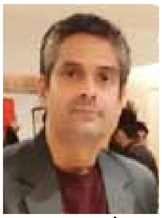

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में जश्न मनाया और अपनी उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान राज्य पार्टी के एकाध नेता 3 साल के जश्न में साथ भले ही नजर नहीं आए लेकिन उनकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी भेज कर बधाई संदेश के साथ आशीर्वाद भी दे दिया। प्रधानमंत्री की भेजी बधाई पाकर सीएम धामी पूरे आत्मविश्वास के साथ दो साल के भीतर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। सीएम धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर प्रदेश में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देहरादून से लेकर राज्य के दूरस्थ गांवों तक जश्न का माहौल दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में अपने विकास कार्यों की जनता को उपलब्धियां भी बताई। मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को भी जनता के सामने रखा, जिनमें समान नागरिक संहिता उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जिसने इसे लागू किया। नकल विरोधी कानून, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे सख्त कानून लागू किया गया। लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई, प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए गए। इसके साथ उन्होंने आगामी 2 साल में राज्य के विकास में क्या-क्या करना है, उसका भी खाका खींचा। कुंवर राज अस्थाना और शंभू नाथ गौतम की रिपोर्ट।

चेहरे पर पहले जैसी चमक बरकरार, बातों में पूरा आत्मविश्वास। पार्टी हाईकमान में भी पहले जैसी पकड़ आज भी बनी हुई है। हर दिन नए जोश के साथ आगे बढ़ते हुए। किसी भी व्यक्ति के पास यह तभी होता है जब सब कुछ ठीक हो। बात हो रही है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। पिछले दिनों सीएम धामी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में जश्न मनाया और अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान राज्य पार्टी के एकाध नेता 3 साल के जश्न में साथ भले ही नजर नहीं आए लेकिन उनकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी भेज कर बधाई संदेश के साथ आशीर्वाद भी दे दिया। प्रधानमंत्री की भेजी बधाई पाकर सीएम धामी पूरे आत्मविश्वास के साथ दो साल के भीतर साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर प्रदेश में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देहरादून से लेकर राज्य के दूरस्थ गांवों तक जश्न का माहौल दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 3 साल होने पर राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में अपने विकास कार्यों की जनता को उपलब्धियां भी बताई। इसके साथ उन्होंने आगामी

पिछले तीन वर्षों में उत्तराखंड में सेवा, सुशासन और विकास के स्थापित हुए नए आयाम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्तमान सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में आयोजित चिकित्सा एवं बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग किया। सेवा सुशासन और विकास की थीम पर आधारित इस आयोजन में मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों एवं आन्दोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि बीते तीन सालों में हमने राज्य को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया है। विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत अल्मोड़ा की इस पुण्य धरा में आयोजित यह कार्यक्रम जन उपयोगी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सेवक के रूप में शपथ लेते ही उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक हम राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में विकसित और आत्मनिर्भर नहीं बना देते है तब तक चौन से नहीं बैठेंगे। हमने अब तक विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य हित से जुड़े निर्णय लेने में पीछे नहीं हटेगी इसी का प्रमाण है कि हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करके देश में नया कीर्तिमान बनाया है। राज्य में सशक्त भू कानून लाकर उत्तराखंड को संरक्षित करने का काम किया है। पिछले तीन वर्षों में उत्तराखण्ड में सेवा, सुशासन और विकास के नये आयाम स्थापित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों को इन्फ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का काम मजबूती के साथ किया है। पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा औद्योगिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित ऐसी 30 नितियां बनाकर राज्य में निवेश को आकर्षित करने का कार्य किया है। जहां हम एक ओर राज्य की मुख्य समस्या पलायन से निपटने की दिशा में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं वहीं रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना सहित अनेक योजनाओं के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा के करबला में पहुंचकर राम कृष्ण मिशन द्वारा निर्मित स्वामी विवेकानंद द्वार का भी लोकार्पण किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए उनके आदर्शों के अनुरूप कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे ही नहीं बल्कि विश्व के आदर्श हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भारी बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर पशुपालन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई जिला बछिया योजना का भी शुभारंभ कर गौमाता की पूजा की तथा गुड एवं चारा खिलाकर गौ सेवा एवं संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को एक मजबूत एवं सशक्त राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल को बेमिसाल बताया तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की संकल्पना को दोहराया।

2 साल में राज्य के विकास में क्या-क्या करना है, उसका भी खाका खींचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर सरकार का प्रहार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान अनेक चुनौतियां सामने आई, लेकिन उनका जनता के बीच खड़े होकर सामना किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन के अनुसार ही उत्तराखण्ड प्रगति कर रहा है। निश्चित तौर पर यह दशक उत्तराखण्ड का होगा। तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और भविष्य के लिए अपनी प्राथमिकताओं को भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि भाजपा की सरकार वापसी नहीं कर पाएगी। क्योंकि इस तरह की परिपाटी नहीं रही है। मगर जनता ने भाजपा को आशीर्वाद देकर फिर से राज सौंप दिया। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष में सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां आईं, लेकिन सरकार ने धरातल पर जाकर उसका सामना किया। रैणी, सिलक्यारा, केदार घाटी से लेकर हालिया माणा की आपदा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के समय पीछे रहकर काम नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 में जिस विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए उत्तराखण्ड पूरी सार्मथ्य से काम कर रहा है। उन्होंने कनेक्टिविटी के विस्तार की बात करते हुए कई उदाहरण दिए और कहा कि उत्तराखण्ड अपनी क्षमताओं का आंकलन करते हुए इसी अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में अवैध निर्माण, कब्जों, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भ्रष्टाचार पर और सख्त प्रहार किए जाएंगे। यूसीसी, भू-कानून, नकल विरोधी जैसे कानूनों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महत्वपूर्ण मसलों को ठंडे बस्ते में डालने में यकीन नहीं करती। इसलिए प्रमुख मुद्दों पर फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण समेत लखपति दीदी जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन से मातृ शक्ति के कल्याण के लिए ठोस कदम आगे बढ़ाए गए हैं। आंदोलनकारियों के लिए दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रवासी उत्तराखण्डियों के सम्मेलन के माध्यम से प्रवासियों को राज्य के साथ जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य का पूरे देश में 13 वां स्थान पर आना सुखद संकेत है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो या जी-20 बैठकों का आयोजन उत्तराखण्ड को इन आयोजनों से दूरगामी लाभ मिला है। सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स में देश में पहला स्थान महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा है। उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष में राज्य का सालाना बजट एक लाख करोड़ को पार कर जाना बताता है कि चुनौतियों के बावजूद हम सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में कुंभ और इसके बाद नंदा राजजात का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय खेलो के आयोजन से जुड़ी सफलता की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने चारधाम

यात्रा, शीतकालीन यात्रा समेत राज्य के कई स्थानों पर पहुंचकर पर्यटन विकास में अभूतपूर्व योगदान किया।

फिट इंडिया, फिट उत्तराखंड के अंतर्गत सीएम धामी ने युवाओं से की अपील

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फिट इंडिया, फिट उत्तराखंड रन और साइकिल रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान धामी का एक अलग ही रंग देखने को मिला, जब वे युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। न केवल उन्होंने साइकिल चलाई, बल्कि मैदान में उतरकर युवाओं के साथ पुशअप्स भी लगाए। यह दृश्य युवाओं में जोश भरने वाला था, जहां मुख्यमंत्री ने खुद फिटनेस का संदेश देते हुए प्रदेश के नौजवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। तीन साल पूरे होने के अवसर पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल रोड शो में भाग लिया। सड़कों पर उमड़े जनसैलाब ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। पूरे शहर में उत्साह और उल्लास का माहौल था, जहां लोग अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए एकत्र हुए थे। रोड शो के दौरान धामी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और अपनी सरकार के प्रति उनके विश्वास के लिए आभार जताया।

ऐतिहासिक फैसलों के साथ तीन साल बेमिसाल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार केवल तीन साल की उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदेश को 'विकसित उत्तराखंड' बनाने के लिए आगे भी इसी गति से कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में राज्य में नए रोजगार के अवसर सृजित करने, पर्यटन को और अधिक समृद्ध बनाने, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू करने और आधारभूत संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को भी जनता के सामने रखा, जिनमें समान नागरिक संहिता उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जिसने इसे लागू किया। नकल विरोधी कानून, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे सख्त कानून लागू किया गया। लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई, प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए गए। चारधाम यात्रा का विस्तार, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बड़े विकास कार्य किए गए। बुनियादी ढांचे में सुधार, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, पर्वतमाला रोपवे परियोजना जैसी योजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 उत्तराखंड में रिकॉर्ड निवेश आया, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिला। उन्होंने उत्तराखंड में सुशासन, विकास और सामाजिक समरसता की मजबूत नींव रखी है। इस अवधि में सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिला।

सीएम धामी ने की छात्रों-युवाओं, उपनल और संविदाकर्मियों के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं

तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों-युवाओं, उपनल और संविदाकर्मियों के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। एक समर्पित मंच के माध्यम से उनके रोजगारपरक कौशल को विकसित करने लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए, सरकार एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी। उपनल एवं संविदाकर्मियों को नियमित नियुक्ति के लिए शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा, दस करोड़ रूपये तक के सरकारी कार्य प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। सेवा, सुशासन और विकास के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं कीं।

पीएम मोदी ने सीएम धामी को भेजी चिट्ठी, कर्मठ और ऊर्जावान का दिया संदेश

मुख्यमंत्री धामी के सेवा सुशासन और विकास के 03 साल के जश्न के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में पीएम मोदी ने धामी को ऊर्जावान मुख्यमंत्री बताया है। इस चिट्ठी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्साह में और अधिक संचार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की यह चिट्ठी धामी सरकार के 3 साल होने पर प्रधानमंत्री ने यह चिट्ठी मुख्यमंत्री धामी को भेजी है। चिट्ठी में सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम धामी की खूब तारीफ भी की गई है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी को कर्मठ और ऊर्जावान बताया।

विकास पुस्तिका 'सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष' का किया विमोचन

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका 'सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष' का विमोचन किया। इसमें सरकार द्वारा 03 साल में जनहित में लिये गये फैसले, योजनाएं और उपलब्धियां शामिल की गई हैं। 'देवभूमि रजत उत्सव-संकल्प से सिद्धि' कलेण्डर का डिजिटल विमोचन और कंटेंट क्रिएटर कंपटीशन का डिजिटल शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाल भिक्षावृति निवारण प्रयास के अन्तर्गत इंटेन्सिव केयर सेंटर साधूराम इण्टर कॉलेज देहरादून में प्रवेशरत शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े 13 बच्चों को सम्मानित किया गया। लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के तहत अधिग्रहित की गई भूमि के भू स्वामियों को अनुग्रह अनुदान के रूप में कुल 10 करोड़ की धनराशि वितरित की गई। अटल आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने चेक और चाबी सौंपी। राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया और सराहनीय कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किये। कार्यक्रम के दौरान सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर कलाकारों द्वारा राज्य की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई।

मोदी सरकार का वक्फ बोर्ड पर 'कंट्रोल'

केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में अब तक सबसे ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगा दी। बजट सत्र के दूसरे चरण में मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा लिया। हालांकि इस विधेयक को पारित करने के लिए पिछले काफी समय से भाजपा और आरएसएस में पटकथा लिखी जा रही थी। इसी महीने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की संघ मुख्यालय नागपुर में मुलाकात भी हुई थी। दोनों की मुलाकात के बाद ही अटकलें का दौर भी शुरू हो गया था कि जल्द ही केंद्र कोई नया ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहा है। बिल कानून बनने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया। अब आने वाले समय में यह विधेयक कानून बन जाएगा और सरकार का वक बोर्ड पर 'कंट्रोल' हो जाएगा। सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष को जवाब देने के लिए गृहमंत्री अमित शाह दोनों मोर्चा संभाले रहे। केंद्र सरकार ने यह बिल ऐसे समय संसद से पास किया है जब भाजपा रविवार 6 अप्रैल को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। केंद्र के इस ऐतिहासिक फैसले से आरएसएस जरूर खुश होगा। वरिष्ठ पत्रकार शंभू नाथ गौतम की खास रिपोर्ट...

अंत भला तो सब भला। देर आए दुरुस्त आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शायद केंद्र की मोदी सरकार से यही कहा होगा। आरएसएस यह भी जानता था कि इस बार मोदी सरकार अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकी। केंद्र की भाजपा सरकार बनाने में इस बार चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का अहम रोल है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में अब तक सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगा दी। मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा लिया। हालांकि इस विधेयक को पारित करने के लिए पिछले काफी समय से भाजपा और आरएसएस में पटकथा लिखी जा रही थी। इसी महीने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की संघ मुख्यालय नागपुर में मुलाकात भी हुई थी। दोनों की मुलाकात के बाद ही अटकलें का दौर भी शुरू हो गया था कि जल्द ही केंद्र कोई नया ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध का खतरा अपनी ही सरकार में शामिल जेडीयू और टीडीपी से था। ऐनमौके पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी भाजपा ने मना लिया। 31 जनवरी से शुरू हुए संसद के बजट सत्र में केंद्र ने कई विधेयक पारित किए। संसद का पहला बजट सत्र 13 फरवरी को समाप्त हो गया। दूसरा बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हुआ। दूसरे सत्र में भी मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक सदन में पेश करेगी या नहीं, आखिरी समय तक सस्पेंस बना रहा। बजट सत्र का दूसरा चरण खत्म होने से एक दिन पहले यह विधेयक दोनों सदनों से पारित कराया गया। बिल को केंद्र की सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने समर्थन दिया। वहीं, विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर कई आपत्तियां उठाईं। विपक्ष का कहना था कि यह वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करेगा और मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकार का अतिक्रमण होगा। इससे पहले चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह भारत सरकार का कानून है और इसे सभी को स्वीकार करना होगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह समाज में भ्रम फैला रहे हैं और मुसलमानों को डराकर उनका वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल कानून बनने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया। अब आने वाले समय में यह विधेयक कानून बन जाएगा सरकार का अब वक्फ बोर्ड पर 'कंट्रोल' हो जाएगा। केंद्र सरकार ने यह बिल ऐसे समय संसद से पास किया है जब भाजपा रविवार 6 अप्रैल को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से आरएसएस जरूर खुश होगा। इस विधेयक के कानून बनने पर जहां भाजपा सरकार गदगद है वहीं विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन विरोध जता रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के धार्मिक और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के विविधतापूर्ण ताने-बाने में वक्फ बोर्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन यह अब तक पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाई है। इस्लामी आध्यात्मिक परंपरा में गहराई से समाई हुई यह वैधानिक इकाई भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बदलने की क्षमता रखती है। हालांकि अपनी समृद्ध विरासत और विशाल भूमि संपत्तियों के बावजूद वक्फ अक्षमताओं, कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी की वजह से पिछड़ गया है। यह वास्तव में विरोधाभासी है कि भारत में तीसरी सबसे बड़ी भूमि स्वामित्व

ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया 'असंवैधानिक कृत्य'

वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने बिल को 'असंवैधानिक कृत्य' बताते हुए वक्फ संशोधन विधेयक की प्रति फाड़ दी। ओवैसी ने कहा, 'हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों की धार्मिक संपत्तियों को संरक्षण प्राप्त है, लेकिन मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों को इस विधेयक के माध्यम से सरकार जब्त करना चाहती है।' ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षणिक प्रगति को रोकने के लिए मुस्लिम वक्फ संपत्तियों को इसलिए कमजोर कर रही है। ओवैसी ने बताया कि साल 2007 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि सिर्फ दिल्ली में 123 वक्फ संपत्तियों की बाजार कीमत 6000 करोड़ रुपये थी, लेकिन अब सरकार इन संपत्तियों को हड़पने के लिए नए कानून बना रही है। ओवैसी ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने से वक्फ संपत्तियों पर कब्जे को कानूनी मान्यता मिल जाएगी।

वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पारित, राष्ट्रपति की मुहर के बाद बन जाएगा कानून

वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद 3 अप्रैल को राज्यसभा से भी पास हो गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह देश में कानून बन जाएगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल पर करीब 13 घंटे तक चर्चा चली। यह विधेयक लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद पारित हुआ था। राज्यसभा में विधेयक को लेकर वैसे तो भारी हंगामा और विपक्ष के कड़े विरोध की उम्मीद थी, लेकिन लोकसभा में विधेयक पारित होने और सरकार की ओर से विधेयक को मुस्लिमों के हित में होने को लेकर जिस तरह के तर्क दिए गए, उससे शायद विपक्ष के हौसले थोड़े पस्त थे। यही वजह थी कि सदन में विधेयक पेश होने के दौरान विपक्ष ने किसी तरह की टोकाटाकी या शोरशराबे से भी परहेज किया। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष की अधिकांश सीटें खाली दिखीं, जबकि सत्ता पक्ष की सीटें खचाखच भरी हुई थीं। इस दौरान लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभाले दिखे। चर्चा के दौरान उन्होंने कई बार खड़े होकर न सिर्फ हस्तक्षेप किया, बल्कि विपक्ष को आईना भी दिखाया। बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया और विरोध में 95 वोट दिया। इससे पहले बुधवार देर रात को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ था। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े थे और विरोध में 232 वोट मिले थे। जेपी नड्डा ने वक्फ अधिनियम से निपटने के तरीके को लेकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। नड्डा ने कहा- हमने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में वक्फ बिल को लेकर कहीं ज्यादा गंभीरता दिखाई। यह बिल पार्टी इंट्रेस्ट का नहीं है, यह नेशनल इंट्रेस्ट का विषय है। विषय को डिरेल नहीं करना चाहिए। जेपी नड्डा ने वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का जोरदार बचाव किया और राष्ट्रीय हितों की रक्षा और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया, जिससे गरीब मुसलमानों का कल्याण होना चाहिए। राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और इसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। फिर भी हमने इसमें गैर-मुस्लिमों की संख्या सीमित कर दी है। वक्फ विधेयक से मुसलमानों को हम नहीं डरा रहे, बल्कि विपक्षी पार्टियां डरा रही हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कानून का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना और सभी मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना है। कहा कि यह विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनका उत्थान करने वाला है। रिजीजू ने जहां विधेयक की खूबियां गिनाई, वहीं विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का भी जवाब दिया। रिजीजू ने कहा कि यह विधेयक गरीब व पिछड़े मुस्लिमों और उनके परिवारों के विकास का रास्ता खोलने वाला है। इसलिए इसका नाम उम्मीद रखा गया है। उन्होंने उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) का पूरा नाम भी पढ़कर बताया। कहा कि वैसे भी जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को विकसित बनाने की बात करते हैं, तो उससे मुस्लिम अलग नहीं हैं।

वाली इकाई के रूप में वक्फ एक ऐसे समुदाय की देखरेख करता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के मुद्दों से जूझ रहा है। सदियों पहले स्थापित वक्फ का मूल उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के लिए स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय और अन्य परोपकारी संस्थानों की स्थापना और देखरेख करना था।

यह चिंता का विषय है कि इतना विशाल संसाधन आधार होने के बावजूद इन्हें समुदाय के कल्याण के लिए प्रभावी रूप से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। ऐसे में वक्फ बोर्ड में सुधार अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में व्यापक रूप से यह सहमति बन चुकी है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है। वक्फ बोर्ड की अक्षमताओं के कारण इन संपत्तियों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पाया है। कई संरक्षकों की अयोग्यता के चलते वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी ने अक्षमताओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित होने पर कहा कि यह विधेयक पारदर्शिता, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन और न्यायिक सुधारों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करना है।

कुट्टू के आटे ने मचाया कोहराम

मिलावटखोरों ने सीएम धामी का किया 'मूड ऑफ'

प्रशासन ने हिलाई गोरखधंधे की बुनियाद

मिलावट ने हमारे जन जीवन को जहरीला बना दिया है। मिलावटखोर त्योहारी सीजन में ज्यादा ही सक्रिय हो जाते हैं और रातोंरात धनवान बनने का सपना देखते हैं। उत्तराखंड में भी मिलावट का खेल काफी समय से चल रहा है। पिछले महीने होली के त्योहार पर भी मिठाइयों, घी, खोया, पनीर, दूध में खूब मिलावट की। हालांकि ऐसा नहीं है कि होली पर धामी सरकार की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई हो उसके बावजूद मिलावटखोर आदत से बाज नहीं आए। हद जब हो गई जब धार्मिक पर्व चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कुट्टू के आटे में भी जहरीला पदार्थ मिला दिया गया। राजधानी देहरादून और हरिद्वार में 350 से अधिक लोग कुट्टू के आटा खाने से बीमार पड़ गए। अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठे तो एक्शन में आए सीएम धामी ने खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छापेमारी करने के आदेश जारी कर दिए। स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार के निर्देश पर विभाग ने सभी 13 जनपदों में ताबड़तोड़ छापे मारे और धरपकड़ की। पंद्रह सौ से अधिक दुकानों पर की छापेमारी की गई। मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड में अब बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा। प्रदेश में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

देश में खाने-पीने की चीजों में व्यापक पैमाने पर मिलावट हो रही है आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। मिलावट ने हमारे जन जीवन को जहरीला बना दिया है। मिलावटखोर त्योहारी सीजन में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो जाते हैं और रातोंरात धनवान बनने का सपना देखते हैं। अपना यह सपना साकार करने के लिए वे बिना सोचे-समझे मिलावट का सहारा लेते हैं। सस्ती चीजों का मिश्रण कर सामान को मिलावटी कर महंगे दामों में बेचकर लोगों को न केवल धोखा दिया जाता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से प्रतिवर्ष हजारों लोग विभिन्न बीमारियों का शिकार होकर जीवन से हाथ धो बैठते हैं। मिलावट का धंधा हर तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी मिलावट का खेल काफी समय से चल रहा है। पिछले महीने होली के त्योहार पर भी मुनाफाखोरों ने खूब जमकर मिलावट की। हालांकि ऐसा नहीं है कि होली पर धामी सरकार की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई हो उसके बावजूद भी वह आदत से बाज नहीं आए। फेस्टिव सीजन में मिठाइयों, घी, खोया, पनीर समेत दूध से बने उत्पादों की मांग बहुत बढ़ जाती है और इसी स्थिति का फायदा मिलावटखोर उठाते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से होली के पर्व पर मिलावटखोरों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन न होने वजह से उनके हौसले बुलंद थे। लेकिन हद जब हो गई जब धार्मिक पर्व चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कुट्टू के आटे में भी जहरीला पदार्थ मिला दिया गया। राजधानी देहरादून और हरिद्वार में 350 से अधिक लोग कुट्टू के आटा खाने से बीमार पड़ गए। बड़ी मात्रा में कुट्टू का आटे का सेवन किया गया था जिस वजह से यह स्थिति बनी। राजधानी के कोरोनेशन और दून अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती कराया गया। सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून जिला अस्पताल में जाकर बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना। नवरात्र पर्व पर हुई इस घटना से धामी सरकार का मूड ऑफ हो गया। अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी किरकिरी हुई। विपक्ष ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला। अस्पताल में मरीजों का हाल-चाल लेने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री धामी एक्शन में आ गए। मुख्यमंत्री धामी ने कड़े शब्दों में चेतावनी जारी करते हुए कहा मिलावट कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सीएम के निर्देश पर खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छापेमारी करने के आदेश जारी कर दिए। स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री

पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दूषित कुट्टू के आटे से अस्पतालों में भर्ती मरीजों के प्रकरण की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया है। यह समिति तीन दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस समिति के अध्यक्ष ताजबर सिंह, अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन होंगे। अन्य सदस्यों में राजेंद्र सिंह रावत, उपायुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सतर्कता सह अभिसूचना शाखा के अधिकारी तथा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नामित दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि समस्त पहलुओं की गहन जांच कर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपयुक्त सुझाव भी रिपोर्ट में शामिल करने को कहा गया है। इससे पहले, 31 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री को दूषित कुट्टू के आटे से बीमार मरीजों से जुड़ी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे खाद्य उत्पादों की खरीद में सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।

एफडीए की टीमों ने 13 जनपदों में पंद्रह सौ से अधिक दुकानों पर की छापेमारी

खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मिलावटखोरों के खिलाफ मंगलवार को प्रदेशभर में दुकानों और खाद्य गोदामों में छापेमारी की। एफडीए की टीमों ने सभी 13 जनपदों में अब तक पंद्रह सौ से अधिक दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 100 से अधिक सैंपल लिए गए और दो दर्जन से अधिक दुकानों को नोटिस थमाए गए हैं। एफडीए आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत छापेमारी अभियान चलाया गया। राज्य के सभी जनपदों में दूषित कुट्टू के आटे की जांच की गई। आयुक्त ने कहा मिलावटखोरों से सख्ती से निपटेंगे। मिलावटखोरी के खिलाफ जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। एफडीए विभाग के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि कुट्टू के आटे के मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान दुकानों से कुट्टू के आटे समेत कई वस्तुओं के सैंपल लिए गए हैं। मिलावट की आशंका को देखते हुए कई जनपदों में कुट्टू के आटे को बड़ी मात्रा में नष्ट कर दिया गया।

पूरे राज्य में ताबडतोड़ छापामारी

राज्य में निगरानी अभियान जारी रहेगाः डॉ. आर राजेश कुमार

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कुट्टू के आटे की जांच में कई नमूने असुरक्षित पाए गए हैं। अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जनपदों में सघन निरीक्षण और नमूना संग्रहण किये जा रहे हैं। जिसमें कई प्रतिष्ठानों से लिए गए कुट्टू के आटे के नमूने असुरक्षित पाए गए। रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में इन नमूनों की जांच की गई। देहरादून जनपद में मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, विकासनगर से संग्रहित नमूना मिला असुरक्षित। यह कीट व फंगस से विषाक्त पाया गया। ब्लिंक कामर्स प्राइवेट लिमिटेड ऋषिकेश, हरिद्वार जनपद में नटराज एजेंसी, पीठ बाजार, ज्वालापुर और आशीष प्रोविजन स्टोर, खेडी मुबारकपुर, लक्सर से संग्रहित नमूने भी असुरक्षित पाए गए। इनमें मायकोटॉक्सिन विषाक्त पाया गया है। इसके अलावा अनाज मंडी रुडकी स्थित शिवा स्टोर से संग्रहित नमूना अधोमानक मिला। वहीं, जनपद ऊधमसिंहनगर में सिसोना, सितारगंज स्थित जय मैया किराना स्टोर से लिए कुट्टू के आटे के सैंपल में मायकोटॉक्सिन पाया गया। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि इन मिलावटी और असुरक्षित नमूनों को लेकर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य संरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे खुले में कुट्टू का आटा न बेचें और केवल सील पैक व मानकों के अनुरूप उत्पाद ही बिक्री के लिए रखें। इसके अलावा, सभी खाद्य विक्रेताओं को खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यभर में कुट्टू के आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी अभियान शुरू किया हुआ है। आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा रोज अभियान की समीक्षा की जाती है। अधिकारियों के फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाती है। उन्होंने कहा इस अभियान का उद्देश्य मिलावटी और असुरक्षित कुट्टू के आटे की बिक्री को रोकना और जनता को सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 3 अप्रैल को खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न जनपदों में कुट्टू आटे के 7 नमूने और पांच अन्य व्रत में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए। इन नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया, और जांच में 2 कुट्टू के आटे के नमूने असुरक्षित पाए गए। इसके बाद, खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को न्यायालय में वाद दायर करने के निर्देश दिए हैं और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा, हम सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का सेवन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। कुट्टू के आटे की जांच के परिणामों को गंभीरता से लिया गया है और असुरक्षित पाए गए नमूनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। काफी हद तक विभाग ने सभी जनपदों में अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को पूरी तरह रोका जा सके। कुमाऊं मंडल में भी छापेमारी अभियान जारी है। एफडीए की टीम ने उपायुक्त डॉ. राजेंद्र कांडपाल के निर्देशन में विभिन्न जनपदों में छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत में भी दुकानों पर छापेमारी की गयी। हर जनपद में दो टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों ने तीन दर्जन से अधिक सैंपल एकत्रित किये हैं, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया है। ऊधमसिंह नगर से लिए गए एक सैंपल में कीड़े पाए गए। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने भी देहरादून समेत गढ़वाल के सभी जिलों में छापेमारी अभियान लगातार जारी है। देहरादून जिले में भी विशेष निगरानी अभियान चलाया गया, जहां मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने राजपुर रोड, कैनाल रोड, हाथीबडकला, यू कैंट रोड और डाकरा बाजार में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इन प्रतिष्ठानों में खुला या पैक्ड कुट्टू का आटा विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं था। हालांकि, विभाग लगातार निगरानी बनाए रखेगा और किसी भी मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगा।

उत्तराखंड में अब बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

नवरात्रि के दौरान व्रत उपवास में प्रमुखता से उपयोग किए जाने वाले कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कुट्टू के आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटी व संदूषित आटे के कारण होने वाली बीमारियों की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के दिशा-निर्देशों पर राज्य में कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर नई गाईडलाइन जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता खुले में कुट्टू का आटा नहीं बेच सकेगा। इसका विक्रय केवल सील बंद पैकेटों में ही किया जाएगा। इसके अलावा, पैकेट पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार लेबलिंग नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, कुट्टू के आटे की पिसाई की तिथि, पैकेजिंग की तिथि और एक्सपायरी डेट पैकेट पर स्पष्ट रूप से अंकित करना जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त, हर पैकेट पर विक्रेता की खाद्य लाइसेंस संख्या दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कुट्टू का आटा और बीज नहीं बेचा जा सकेगा। सभी खाद्य कारोबारियों को खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होगा। बिना अनुमति के खुले में कुट्टू के आटे की बिक्री करने पर कडी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में देहरादून, हरिद्वार और अन्य जिलों में मिलावटी कुट्टू के आटे के सेवन से कई लोग फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों से ग्रसित होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सरकार ने पहले से ही सख्ती बरतने का फैसला किया है। डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा एफडीए ने सभी जिलों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि नए नियमों का कडाई से पालन हो और इसकी नियमित जांच व निरीक्षण किया जाए। यदि कोई भी विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा नवरात्रि के दौरान कुट्टू के आटे की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं को भी चाहिए कि वे केवल सील पैक आटा ही खरीदें और पैकेट पर अंकित निर्माण व एक्सपायरी तिथि, लाइसेंस नंबर और अन्य विवरणों को ध्यानपूर्वक जांचें।

उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेशभर में लगभग पंद्रह सौ से भी अधिक दुकानों पर छापेमारी की गई है। कई दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा दो दर्जन से भी अधिक दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि विभाग ने यह स्पष्ट किया कि उन दुकानदारों को कड़ी सजा दी जाएगी, जो मिलावट में शामिल पाए जाएंगे। विभाग ने दुकानदारों से शुद्ध सामग्री बेचने की अपील की और कहा कि किसी भी हाल में मिलावट करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने उपायुक्त गढ़वाल आर. एस. रावत और जिला अभिहित अधिकारी के नेतृत्व में रेसकोर्स, आराघर, धर्मपुर, नेहरू कॉलोनी, आढत बाजार, हनुमान चौक सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह, संजय तिवारी, संतोष कुमार सिंह और सतर्कता अभिसूचना एफ. डी.ए. के जगदीश रतूडी समेत पुलिसकर्मी शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान 21 प्रतिष्ठानों में कुट्टू का आटा विक्रय हेतु नहीं पाया गया, केवल गोयल आटा चक्की, रेस्ट कैंप में पैक्ड कुट्टू का आटा बिक्री पर था, जिसका नमूना जांच के लिए लिया गया। जांच दल ने करीब 100 किलो दूषित कुट्टू के आटे को जब्त कर कारगी ट्रेंचिंग ग्राउंड में नष्ट कर दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय सतर्क रहें और संदिग्ध खाद्य पदार्थों की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें। डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि यह केवल विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम जनता को भी मिलावटखोरों के खिलाफ जागरूक होने की जरूरत है। जागरूकता से ही मिलावटखोरी समाप्त की जा सकती है। लोगों को यह समझना होगा कि मिलावटी खाद्य पदार्थ उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकते हैं।

दि एसोसिएशन ऑफ ओटोलेरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, उत्तराखंड शाखा का 18वां वार्षिक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न

यह सम्मेलन एओआई देहरादून शाखा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. आलोक जैन (अध्यक्ष, USAOI), डॉ. एस. एस. बिष्ट (सचिव, USAOI), डॉ. अनूप कौशल (आयोजन अध्यक्ष), डॉ. अश्विन गर्ग (आयोजन सचिव), डॉ. विनीश अग्रवाल (संयुक्त आयोजन सचिव) और डॉ. चेतन बंसल (कोषाध्यक्ष) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर राज्य एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. डी. एम. काला को ईएनटी के क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड एवं आसपास के राज्यों से 100 से अधिक ईएनटी सर्जनों ने भाग लिया।

देश ने खो दिया देशभक्त कलाकार 'भारत कुमार'

भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार रहे मनोज कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड में मनोज कुमार एक ऐसे कलाकार थे जो अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। अभिनेता मनोज कुमार की अधिकांश फिल्मों में देशभक्ति की झलक भी झलकती थी। इसी वजह से उन्हें 'भारत कुमार' कहा जाता था। उनकी यादगार फिल्मों की बात करें, तो उसमें 'क्रांति', 'उपकार', 'शहीद', 'पूरब और पश्चिम' के अलावा 'रोटी कपड़ा और मकान' समेत कई फिल्में शामिल हैं। 'पूरब और पश्चिम' फिल्म का गीत 'भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं'। आज भी सभी की जुबां पर हैं। कला क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उनकी विरासत में चार चांद तब लगे, जब 2015 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं और अभिनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

शुक्रवार 4 अप्रैल 2025 फिल्म इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की बड़ी क्षति हुई है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार रहे मनोज कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड में मनोज कुमार एक ऐसे कलाकार थे जो अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। अभिनेता मनोज कुमार की अधिकांश फिल्मों में देशभक्ति की झलक भी झलकती थी। इसी वजह से उन्हें 'भारत कुमार' कहा जाता था। फिल्मी दुनिया को सबसे ज्यादा देशभक्ति वाली फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार नहीं रहे। दशकों तक सिनेमा पर राज करने वाले मनोज कुमार ने 87 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। मनोज कुमार के निधन से फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ पूरे देश भर में शोक का माहौल है। मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने बताया, 'उन्हें लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थीं। यह भगवान की कृपा है कि उन्हें आखिरी समय में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, शांतिपूर्वक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मनोज कुमार को हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लीकेशंस की वजह से कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निधन का दूसरा कारण डीकंपेंसेटेड लिवर सिरोसिस है। उनकी यादगार फिल्मों की बात करें, तो उसमें 'क्रांति', 'उपकार', 'शहीद', 'पूरब और पश्चिम' के अलावा 'रोटी कपड़ा और मकान' समेत कई फिल्में शामिल हैं। 'पूरब और पश्चिम' फिल्म का गीत 'भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं'। आज भी सभी की जुबां पर हैं। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गोस्वामी और उनका जन्म ऐबटाबाद (अब पाकिस्तान) 1937 में हुआ था। एक्टर की देशभक्ति वाली इतनी फिल्में इतनी हिट रहीं कि उनका नाम ही 'भारत कुमार' पड़ गया। उनके निधन की खबर सुनने के बाद हर कोई सदमे में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्टर के साथ अपनी यादगार तस्वीरें भी शेयर कीं। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में कहा, 'महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार' के निधन से बहुत दुःख हुआ। वे भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे, जिन्हें खासतौर पर उनकी देशभक्ति के जोश के लिए याद किया जाता था, जो उनकी फिल्मों में भी झलकता था। उनके कामों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाया। वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। उनके निधन की खबर ने फिल्म उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई है। पूरे देश में दुख का माहौल है। लोग ने उनके निधन पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा के अभिनेता प्रेम चोपड़ा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजय देवगन, अक्षय कुमार, पूनम ढिल्लो और रवीना टंडन ने मनोज कुमार को श्रद्धांजलि दी। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भी दिग्गज अभिनेता के निधन पर अपना दुःख जताया। उन्होंने कहा, 'आप सभी को यह बताते हुए दुख हो रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता, हमारे प्रेरणास्रोत, भारतीय फिल्म उद्योग के दिग्गज, मनोज कुमार जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक अस्वस्थ रहने के बाद अंधेरी के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली। यह बहुत बड़ी क्षति है, आप बहुत याद आएंगे।' एक्टर मनोज कुमार ने बंटवारे के दर्द को अपनी आंखों से देखा था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1957 में आई फिल्म 'फैशन' से की थी। इसके बाद 1960 में उनकी फिल्म 'कांच की गुड़िया' रिलीज हुई। मनोज कुमार ने 'उपकार', 'पत्थर के सनम', 'रोटी कपड़ा और मकान',

'संन्यासी' और 'क्रांति' जैसी कमाल की फिल्में दीं थी। उनकी पहली रिलीज देशभक्ति फिल्म 'शहीद' थी, जो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के साथ-साथ भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री से भी जमकर तारीफ मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। बचपन से ही मनोज कुमार, दिलीप कुमार के बड़े प्रशंसक थे। दिलीप साहब की फिल्म शबनम (1949) मनोज कुमार को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने उसे कई बार देखा। फिल्म में दिलीप कुमार का नाम मनोज था। जब मनोज कुमार फिल्मों में आए तो उन्होंने दिलीप कुमार के नाम पर ही अपना नाम भी मनोज कुमार कर लिया।

लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर मनोज कुमार ने बनाई थी फिल्म उपकार

मनोज कुमार के कलाकारों के साथ-साथ राजनेताओं से भी अच्छे संबंध थे। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद ही मनोज कुमार ने लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अभिनेता से युद्ध से होने वाली परेशानियों पर एक फिल्म बनाने के लिए कहा। हालांकि, उन दिनों तक अभिनेता को फिल्म बनाने का अनुभव नहीं था। इसके बावजूद अभिनेता ने 'जय जवान जय किसान' से संबंधित 'उपकार' फिल्म बनाई, जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। हालांकि, इस फिल्म को खुद लाल बहादुर शास्त्री नहीं देख पाए थे। ताशकंद से लौटने के बाद लाल बहादुर शास्त्री इस फिल्म को देखने वाले थे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। 'उपकार' (1967) बनाई, जिसे क्रिटिक्स की खूब तारीफें मिली और यह उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी। इस फिल्म का संगीत 1960 के दशक का छठा सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी फिल्म एल्बम था। फिल्म 'उपकार' का एक गीत, 'मेरे देश की धरती' हर साल भारत में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बजाया जाता है। राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर (1970) में मनोज कुमार ने काम किया। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, तो मनोज कुमार ने राज कपूर को समझाया कि फिल्म की लेखनी बेहद कमजोर थी। अगर स्क्रिप्ट पर काम होता तो फिल्म हिट होती। राज कपूर ने भी इस बात को कबूल कर लिया। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई श्रेणियों में सात फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। कला क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्म श्री से सम्मानित किया। उनकी विरासत में चार चांद तब लगे, जब 2015 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है।

यूजीवीएन लिमिटेड की 118 वर्ष पुरानी गलोगी लघु जल विद्युत परियोजना द्वारा स्थापना के बाद से अब तक का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन

उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसूरी के पास स्थित यूजेवीएन लिमिटेड की गलोगी जल विद्युत परियोजना द्वारा एक शताब्दी से भी अधिक के अपनी स्थापनाकाल के बाद से अब तक का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए यूजीवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप सिंघल ने बताया कि जनपद देहरादून में मसूरी मार्ग पर क्यारकुली व भट्टा गांव के बीच स्थित 3.50 मेगावाट स्थापित क्षमता की गलोगी जल विद्युत परियोजना द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8.075 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया है जो कि परियोजना के निर्माण के बाद से अब तक के किसी भी वर्ष का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन है। इससे पूर्व इस परियोजना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया गया 7.96 मिलियन यूनिट किसी भी वित्तीय वर्ष का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन था। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा इस परियोजना को एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह सहेजते हुए संचालन किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि गलोगी लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना तत्कालीन ब्रिटिश शासन काल में सन् 1907 में की गई थी जिसका प्रमुख उद्देश्य मसूरी क्षेत्र में विद्युत एवं जल की आपूर्ति किया जाना था। उस दौर में कलकत्ता, दार्जिलिंग और शिमला के बाद संभवतः मसूरी में ही विद्युत वितरण व्यवस्था उपलब्ध थी। यह परियोजना ब्रिटिश काल में स्थापित चंद जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है तथा इकलौती ऐसी परियोजना है जो आज भी सफलतापूर्वक विद्युत उत्पादन के साथ साथ जलापूर्ति के अपने उद्देश्यों को भी पूरा कर रही है। डॉ. सिंघल ने परियोजना के रिकार्ड उत्पादन पर समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए अपेक्षा की कि वह भविष्य में भी इसी मनोयोग एवं समर्पण से कार्य करते हुए विद्युत उत्पादन के नए आयाम स्थापित करते रहेंगे।

नवनियुक्त मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन का दमदार आगाज

राज्य में रेल सुविधाओं के विकास, 2027 के कुंभ एवं चारधाम यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा ब्यूरोक्रेसी को किया एलर्ट

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने परिवहन विभाग को राज्य में प्रस्तावित सभी रेल परियोजनाओं की स्थिति पर अपडेट देने एवं वर्तमान में संचालित रेल परियोजनाओं में आ रही बाधाओं व समस्याओं पर बिन्दुवार रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने देहरादून सहित सभी रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन की स्थिति भी स्पष्ट करने को कहा है। इसके साथ ही सीएस ने राज्य में प्रस्तावित एवं संचालित रेल प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित मुद्दों पर रेल मंत्रालय, आरवीएनएल सहित सम्बन्धित संस्थाओं से प्रभावी समन्वय के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रें का रेल नेटवर्क से संयोजन, राज्य के औद्योगिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास, विश्व प्रसिद्ध धामों, तीर्थ में वर्ष भर श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन तथा सामरिक महत्व के दृष्टिगत रेलवे का अवसंरचना का राज्य हेतु अत्यंत महत्व है।

परिवहन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में कुल पांच रेल परियोजनाएं हैं जिनमें तीन प्रस्तावित एवं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग सहित दो परियोजनाएं वर्तमान में संचालित की जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना जिसकी कुल दूरी 121.76 किमी है तथा 10 स्टेशन हैं। इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा डीपीआर रेलवे बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। इस पर अनुमोदन प्रतीक्षित है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना जिसकी कुल दूरी 170.70 किमी है तथा 12 स्टेशन हैं। इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा डीपीआर रेलवे बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। इस पर अनुमोदन प्रतीक्षित है। देहरादून -सहारनपुर रेल परियोजना जिसकी कुल दूरी 92.60 किमी0 है तथा इसमें 8 स्टेशन है। इसका सर्वेक्षण कार्य गतिमान है। बैठक में सचिव परिवहन, अपर सचिव परिवहन, सचिव एमडीडीए सहित सम्बनित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

हरिद्वार पहुंचकर आगामी 2027 कुंभ और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने हरिद्वार में आगामी कुंभ-2027 के मेले को लेकर मेला अधिकारी कर्मेन्द्र सिंह से मायापुर स्थित कैंप कार्यालय में विचार विमर्श किया। उन्होंने जिलाधिकारी एंव जनपदीय अधिकारीयों को आगामी कुंभ-2027 की तैयारियों के सम्बंध में निर्देश दिए कि शासन स्तर पर भी आगामी सात-आठ दिन में बैठक की जाएगी जिसमें कुंभ- 2027 में सरकार द्वारा सुचारू व्यवस्था की जाएगी, साधु संतों और महात्माओं को साथ में लेकर और उनके मार्गदर्शन व विचार विमर्श कर आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आगामी कुंभ-2027 को लेकर हमारी योजनाएं गतिशील है जो भी योजनाएं बनेगी वह हरिद्वार शहर कुंभ नगरी के हित में होगी।

मुख्य सचिव ने चार धाम यात्रा को लेकर अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थाएं सुचारू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिला प्रशासन के स्तर और शासन के स्तर पर भी जहां-जहां जो आवश्यकताए है, वह पूरी की जा रही है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। सभी हितधारकों के साथ भी विचार विमर्श शुरू हो चुका है और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा मौके पर निरीक्षण किया जा रहा है। चारों धाम पर जहां-जहां उनके यात्रा मार्ग पर जो आवश्यकता होगी वो पूरी करने की कोशिश की जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा के आरंभ में अधिक से अधिक दर्शनार्थी पहुँते हैं, अतः हम सभी राज्यों, प्रमुख व्यक्तियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों से अनुरोध करते हैं कि इस दौरान यात्रा न करे, लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा समुचित व्यवस्थाएं की जाएगी, जिससे चार घाम यात्रा सकुशल सम्पन्न हो सके।

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने कहा कि 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर सभी योजनाओं की रूपरेखा बनाई जा रही है और समस्त योजनाएं हरिद्वार के हित में होंगी। गौरतलब है कि मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन पूर्व में हरिद्वार जनपद के जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष भ्त्क्षए और वर्ष 2010 में हुए कुंभ के मेलाधिकारी भी रहे हैं। हरिद्वार में पत्रकारों से अनौपचारिक संवाद के दौरान सीएस ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन स्तर से कई अधिकारी फील्ड में गए हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। मीडिया द्वारा पूर्ण कुंभ के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पूर्ण कुंभ के लिए साधु- संत और महात्मा लोगो से विचार विमर्श के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके पश्चात मुख्य सचिव ने जूना अखाड़ा स्थित श्री माया देवी मंदिर, कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर के बाद गंगा आरती में प्रतिभाग किया। इस दौरान जिलाधिकारी, एसएसपी मुख्य विकास अधिकारी सहित

सभी जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

विभागों को बजट प्रावधान के अनुरूप राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए

नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज सचिवालय में आयोजित अपनी पहली सचिव समिति की बैठक में सभी विभागों को बजट प्रावधान के अनुरूप राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएस ने पूंजीगत मद पर व्यय बढ़ाने के लिए प्रयास के साथ विभागों को अपनी वार्षिक कार्य योजना पहले से ही तैयार करने तथा प्रत्येक माह का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों से अपेक्षा की गई है कि वार्षिक कार्ययोजना में भौतिक एवं वित्तीय, आउटकम एवं आउटपुट सम्बन्धित सूचनाएं समाहित करें। आज की बैठक में मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय, लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभाग आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्ताव पहले से तैयार रखे। उनके द्वारा विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले अवस्थापना विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं का चिन्हांकन कर ैमर्स वि त्तवरमबजे तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से किये जाने की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने विभागों अपने प्रस्ताव गति शक्ति पोर्टल पर निरन्तर अपडेट करने के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव के निर्देश पर परियोजनाओं के गठन से लेकर उसके कार्यान्वयन तक सभी ।बजपअपजपमे गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से किये जाएगें। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रस्ताव मा0 मंत्रिमण्डल में प्रस्तुत करने से पूर्व पूरी तरह से तैयार करने के साथ ही ससमय भेजे जाए। इसके साथ ही सीएस ने निर्देश दिए हैं कि लैण्ड बैंक ससमय तैयार रखा जाए ताकि प्रस्तावों पर अविलम्ब कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

चारधाम यात्रा मार्ग की पुख्ता व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए निर्देश दिए हैं कि आगामी यात्रा सीजन के दृष्टिगत सभी विभागों को अभी से अपनी तैयारियां समयबद्धता से पूरी करनी हैं। उन्होंने यात्रा मार्ग पर सभी जरूरतों का अभी से आंकलन करते हुए सभी व्यवस्थाएं यात्रा आरम्भ से पहले दुरूस्त करने के निर्देश दिए हैं। सचिव श्री युगल किशोर पंत को देहरादून से केदारनाथ, सचिव डा0 आर राजेश कुमार को बद्रीनाथ यात्रा मार्ग, सचिव डा बी वी आर सी पुरूषोत्तम को गंगोत्री धाम तथा डा0 नीरज खैरवाल को यमुनोत्री धाम की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में सभी प्रमुख सचिव एवं सचिव मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर. सी. पुरुषोत्तम ने मंगलवार को सचिवालय में नव नियुक्त मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमति मुक्मा मिश्र, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास उपस्थित रहे।

चारधाम यात्रा में सुरक्षा और सुगमता के लिए आईजी गढ़वाल रेंज को बनाया गया चारधाम यात्रा का नोडल अधिकारी

नोडल अधिकारी एवं चारधाम यात्रा सेल की स्थापना:

• आईजी गढ़वाल रेंज, श्री राजीव स्वरूप को चारधाम यात्रा-2025 का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे यात्रा मार्गों और प्रमुख ठहराव स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबन्धन, भीड़ प्रबन्धन और आपदा से निपटने की तैयारियों की सीधी निगरानी एवं समन्वय करेंगे।

• गढ़वाल रेंज कार्यालय में 'चारधाम यात्रा कन्ट्रोल रूम' स्थापित किया जा रहा है, जिसके प्रभारी एसपी ट्रैफिक देहरादून, श्री लोकजीत सिंह होंगे। कन्ट्रोल रूम में 01 पुलिस उपाधीक्षक, 02 निरीक्षक, 04 उपनिरीक्षक, व हेड कान्स./ कान्स. की नियुक्ति की जायेगी। यह सेल 24 घण्टे कार्यरत रहेगा। इस कन्ट्रोल रूम में रजिस्ट्रेशन, ट्रैफिक प्रवाह, पार्किंग व्यवस्था, डयूटी का व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, यात्री आवाजाही, डेटा प्रबंधन, फर्जी रजिस्ट्रेशन पर कार्यवाही, आपदा प्रबंधन सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय जैसे कार्यों हेतु विशेष डेस्क स्थापित की जाएगी। यह कन्ट्रोल रूम अगले 5 दिनों में पूर्णतः सक्रिय हो जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों को यात्रा की स्थिति की दैनिक अपडेट प्रदान करेगा।

मुख्यालय स्तर पर चारधाम सेल:

• पुलिस मुख्यालय स्तर पर डीआईजी अपराध एवं कानून व्यवस्था, श्री धीरेन्द्र गुंज्याल के नेतृत्व में एक 'चारधाम सेल' गठित किया जाएगा, जो यात्रा से संबंधित सूचनाओं का संकलन एवं समन्वय करेगा।

यात्रा मार्गों का सेक्टरवार विभाजन व पुलिस बल की तैनाती:

पहली बार यात्रा मार्गों का 15 सुपर जोन, 41 जोन तथा 137 सेक्टरों विभाजन, प्रत्येक सेक्टर में पुलिस बल की तैनाती और 24x7 निगरानी
-राजीव स्वरूप, आईजी गढ़वाल

• चारधाम यात्रा को निर्वाध एवं सुरक्षित संचालित किये जाने हेतु इस वर्ष सम्पूण र्ा चारधाम यात्रा मार्ग को 15 सुपर जोन, 41 जोन तथा 137 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक सेक्टर का क्षेत्र 10 किमी रहेगा तथा इन सेक्टरों में 02-02 कान्स राउण्ड द क्लॉक डयूटी पर नियुक्त रहेंगे।

• समस्त यात्रा मार्गो पर 09 अपर पुलिस अधीक्षकों को रूट प्रभारी के रूप में अलग से नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा अपने डयूटी क्षेत्र में यात्रा व्यवस्थायें की जायेंगी, साथ ही प्रत्येक धाम में 01-01 पुलिस उपाधीक्षक को धाम का प्रभारी बनाया गया है, जिनके द्वारा धामों की सम्पूर्ण व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी।

• सम्पूर्ण यात्रा के सकुशल संचालन हेतु 24 पुलिस उपाधीक्षक, 66 निरीक्षक, 366 उपनिरीक्षक, 615 हेड कान्सटेबल, 1222 कान्सटेबल, 208 महिला कान्सटेबल, 926 होमगार्ड, 1049 पी.आर.डी. के जवान, 09 कम्पनी पी.ए.सी. 26 सब टीम एसडीआरएफ की नियुक्ति की जानी प्रस्तावित है।

यातायात एवं पार्किंग प्रबंधन:

• यातायात प्रबंधन हेतु व्यापक रणनीति तैयार की गई है। जिसके तहत पुलिस महानिरीक्षक/ निदेशक यातायात ने स्वयं एवं अपनी टीम के साथ यात्रा मार्गों को स्थलीय निरीक्षण प्रारंभ कर दिया है, तथा यात्रा मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है।

• नए एक्सप्रेसवे के शुभारंभ को देखते हुए यमुनोत्री मार्ग पर अतिरिक्त हॉल्टिंग क्षेत्रों और पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन के साथ समन्वय से की जा रही है।

• ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप की तर्ज पर यमुनोत्री-गंगोत्री धामों के लिए विकासनगर क्षेत्र में एसपी विकासनगर के पर्यवेक्षण में यात्रियों एवं वाहनों का प्रबंधन किया जाएगा।

नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए

नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन राज्यपाल ले.ज. (रि.) गुरमीत सिंह से मुलाकात करते हुए

नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात एवं कुंभ 2027 के लिए वार्ता करते हुए

नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन महामंडलेश्वर राजराजेश्वरानंद से मुलाकात एवं कुंभ 2027 के लिए वार्ता करते हुए

नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरूषोत्तम एवं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय जोगदंडे

नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए देवभूमि पत्रकार यूनियन के उपाध्यक्ष एवं दिव्य हिमगिरि के संपादक कुँवर राज अस्थाना

प्रगति पथ पर अग्रसर: उत्तराखण्ड

❝ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में नई रोपवे परियोजनाओं, रेल, सड़क और हवाई नेटवर्क में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। ये पहल पर्यावरण अनुकूल यात्रा की सुविधा प्रदान करते हैं। यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे। अपने समृद्ध आध्यात्मिक, रोमांचकारी और सांस्कृतिक अनुभवों के साथ, उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करना जारी रखेगा।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

>> कॉर्बेट नेशनल पार्क के दौरे पर मुख्यमंत्री धामी

नये वेडिंग डेस्टिनेशन हब के रूप में निखर रहा उत्तराखंड

उत्तराखंड अपनी सुदंरता के अलावा वेडिंग डेस्टनेशन के लिए भी दुनिया भर में जाना जाने लगा है। यही कारण है कि यहां पर देश और दुनिया भर से लोग वेडिंग के लिए आ रहे हैं और सुनहरी यादें अपने साथ लेकर जा रहे हैं

उत्तराखंड एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार के रणनीतिक विस्तार से जुड़े विभिन्न प्रयासों और हितधारकों के समर्थन से टिहरी ऐसे यादगार कार्यक्रमों के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य बन रहा है। अपनी शादी को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए जोड़े यहां आ रहे हैं।

टिहरी का टेंट सिटी के रूप में विकसित होना इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर काम करने वाला यह उद्यम विवाह के लिए इसे उपयुक्त बना देता है। टिहरी की शांत झील, भव्य टेंट और समकालीन सुविधाओं से इसका युक्त होना विवाह समारोहों के लिए इसे विशेष बना देता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि उत्तराखंड डेस्टिनेश वेडिंग के लिए सबसे तेजी से उभरते राज्यों में एक बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ विवाह स्थल बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार राज्य की असीम संभावनाओं में उनके विश्वास को दर्शाता है। इसलिए उत्तराखंड सरकार टिहरी को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर ध्यान दे रही है। शादियों के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का यह प्रयास सराहनीय है। यह कहीं न कहीं से स्थानीय निवासियों और उद्यमों का भी समर्थन करता है।

टिहरी के आकर्षण को और बढ़ाने के लिए जल्द ही त्रियुगीनारायण मंदिर के लिए एक हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। यह सेवा आगंतुकों, विशेष रूप से इस

PIC: DIPR, UTTARAKHAND GOVERNMENT

पवित्र मंदिर में विवाह करने के इच्छुक जोड़ों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसे पारंपरिक रूप से भगवान शिव और पार्वती के विवाह का स्थल माना जाता है। विवाह की रस्मों के बाद टिहरी के सुरम्य परिवेश में विवाह समारोह को जारी रखा जा सकता है, जो आध्यात्मिकता और उत्सव का सुंदर मेल है।

इसके अलावा, टिहरी के आस-पास के कुछ गांवों को होमस्टे गांवों के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करने का फैसला लिया गया है। ये होमस्टे पारंपरिक आतिथ्य का बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के साथ ही उत्तम सुविधाओं से युक्त हैं। इससे शादी में आए मेहमानों को यहां की संस्कृति को करीब से समझने का भी अवसर मिलता है। धामी सरकार का होमस्टे का यह प्रयास न केवल शादी के अनुभव को और आकर्षक बनाता है, बल्कि नागरिकों के लिए वित्तीय संभावनाएं भी प्रदान करता है। इससे वैवाहिक उत्सव के साथ ही स्थायी पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है।

कोटी कॉलोनी से डोबरा चांटी ब्रिज तक चार लेन की रिंग रोड से कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा, जिससे यह जगह यात्रियों और शादी समारोहों के लिए अधिक सुलभ हो जाएगी। इस रिंग रोड में मनोरम दृश्य और फेरी के लिए विशेष स्थान भी होंगे, जो क्षेत्र के स्थानीय आकर्षण को चार चांद लगाएंगे। यह सड़क चार धाम तीर्थयात्रियों के लिए एक आवश्यक मार्ग के रूप में भी काम करेगी, जिसमें एडवेंचर और सांस्कृतिक पर्यटन के साथ ही आध्यात्मिक पर्यटन का भी पर्यटक लाभ ले सकेंगे।

PIC: DIPR, UTTARAKHAND GOVERNMENT

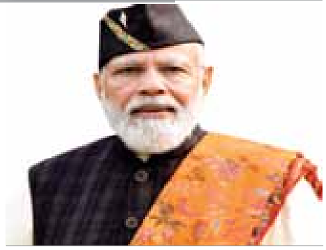

❝ **मैं उत्तराखंड सरकार को पिछले कुछ वर्षों में हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति के लिए बधाई देता हूं। यह पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत फैसलों व इस दिशा में ध्यान देने से संभव हुआ है। राज्य ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे उत्तराखंड सतत विकास के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। अपने प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करने और पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, बल्कि वैश्विक मंच पर इसकी क्षमता को प्रदर्शित भी किया है। मैं समावेशी विकास के लिए राज्य के समर्पण की सराहना करता हूं और आने वाले वर्षों में इसकी निरंतर सफलता की आशा करता हूं।**

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

टिहरी की ऊंची उड़ान: पैराग्लाइडिंग प्रेमियों के लिए उभरता गंतव्य

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने-माने पैराग्लाइडिंग विशेषज्ञों के अनुसार, टिहरी में विश्व स्तरीय पैराग्लाइडिंग केंद्र बनने की क्षमता है। 1500 मीटर से अधिक की आदर्श ऊंचाई, कम हवा की आवाजाही, अनुकूल जलवायु और देहरादून

हवाई अड्डे से आसान पहुंच के साथ, टिहरी-झील को आगामी पैराग्लाइडिंग हब के रूप में देखा जा रहा है।

टिहरी को पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के पर्यटन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्रोबैटिक फेस्टिवल आयोजित कर रहा है। इस फेस्टिवल में 30 से अधिक देशों के 150 से अधिक पैराग्लाइडिंग दिग्गजों ने हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन ने टिहरी को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग मंच में ऊंचा दर्जा दिलाया। साथ ही अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षण समूहों के साथ देखे जा रहे हैं।

राज्य में पैराग्लाइडिंग गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने स्थानीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए जरूरी कौशल और सिक्योरिटी सिर्टीफिकेट देने के लिए टिहरी में पी1, पी2 और एसआईवी जैसे विभिन्न स्तरों की पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग कोर्स शुरू किए हैं। इस कदम से स्थानीय कुशल लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, क्योंकि टिहरी में पैराग्लाइडिंग खेल गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है।

होमस्टे: राज्य में आतिथ्य का भविष्य

होमस्टे के मालिकों को सशक्त बनाकरअर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करना

विभिन्न भौगोलिक और पारिस्थितिक कारकों के चलते राज्य में बड़े होटल स्थापित करना संभव नहीं है। इसलिए उत्तराखंड ने होमस्टे मालिकों को यहां बेहतर होमस्टे बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए विभिन्न सुविधाएं और प्रोत्साहन शुरू किए हैं।

राज्य ने होमस्टे से जुड़ी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजी सहायता प्रदान करना, कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण देना और एक समर्पित होमस्टे बुकिंग पोर्टल www.uttarastays.com शुरू करना शामिल है। इससे होमस्टे मालिकों को बिना किसी एकीकरण शुल्क व कमीशन के अपने होमस्टे को सूचीबद्ध करने की सुविधा मिलती है।

यह रणनीति राज्य से पलायन को रोकने के लिए तैयार की गई है, जिससे ज्यादातर स्थानीय लोग होमस्टे स्थापित कर राज्य पर्यटन विभाग के स्वामित्व वाले पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही यह उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर रहा है।

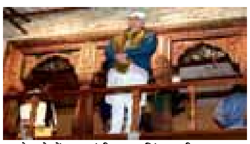

>> होमस्टे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

हिमालय के अंदुरूनी इलाकों में खूबसूरत और मनमोहक स्थल मौजूद हैं, जहां अच्छे होमस्टे ढूंढना अभी भी चुनौती बना हुआ है। स्थानीय लोगों के लिए, जिन्होंने इन जगहों पर होमस्टे यूनिट्स स्थापित की हैं, उनका ऑनलाइन माध्यम से संभावित मेहमानों तक पहुंचना मुश्किल है। uttarastays.com पोर्टल इस अंतर को पाटने और राज्य के सभी होमस्टे के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार है।

PIC: DIPR, UTTARAKHAND GOVERNMENT

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने होमस्टे मालिकों के लिए राज्य में बेहतर होमस्टे बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए विभिन्न सुविधाएं और प्रोत्साहन शुरू किए हैं

सतत और पारिस्थितिकी विकास के नए युग के पर्यटन को अपना रहा उत्तराखंड

नए युग के पर्यटन उत्पादों के साथ उत्तराखंड पर्यटन विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां विकास का मतलब सतत और समावेशी दोनों ही है

उत्तराखंड लंबे समय से योग और स्वास्थ्य गतिविधियों के केंद्र के रूप में पहचाना जाता रहा है, जिसमें ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी दर्जा हासिल है। आयुष विभाग और पर्यटन विभाग की विभिन्न विकासात्मक पहलों के साथ पूरे राज्य में समग्र आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करने वाले स्वास्थ्य केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों को पर्यटन विभाग द्वारा आस-पास के होमस्टे से जोड़कर बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग और आयुष विभाग ने होमस्टे में रहने वाले पर्यटकों के लिए आयुर्वेद आधारित स्वागत किट भी विकसित की है।

होमस्टे से जुड़े स्वास्थ्य केंद्रों को www.uttarastays.com पोर्टल पर सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि इन स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा सके।

इन नए युग के पर्यटन उत्पादों के साथ उत्तराखंड पर्यटन विकास के नए युग की ओर अग्रसर है, जिसमें सतत और समावेशिता दोनों शामिल हैं।

उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023-30

आधुनिक पर्यटन के साथ आध्यात्मिक आनंद

बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर पर्यटन के नए क्षेत्रों को खोलने तक को लेकर राज्य पर्यटन के क्षेत्र में प्रयोग के दौर से गुजर रहा है

PIC: DIPR, UTTARAKHAND GOVERNMENT

>> उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोवा सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए। दोनों राज्यों में समग्र पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

उत्तराखंड देवभूमि के नाम से पहचाने जाने के साथ ही प्राचीन काल से आध्यात्मिकता का केंद्र भी रहा है। गंगा के तट पर हरिद्वार और वहां के मंदिर विशेष पहचान रखते हैं। इस पवित्र शहर से हर साल चार धाम यात्रा का शुभारंभ होता है और कुंभ मेले का आयोजन होता है। यहां शिव और शक्तियों को लेकर अपनी रहस्यमय कहानियां भी हैं। यह स्थल न केवल राज्य के लिए गौरव का विषय है, बल्कि आध्यात्मिक साधकों के लिए एक स्वर्ग जैसा है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर और नए अनुभव बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर पर्यटन के नए क्षेत्रों को खोलने तक को लेकर राज्य पर्यटन के क्षेत्र में प्रयोग के दौर से गुजर रहा है। साथ ही, पर्यटकों के विभिन्न वर्गों को लक्षित करने के लिए पर्यटन उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला भी पेश कर रहा है। पर्यटन के विकास को लेकर प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां की पारिस्थितिकी और प्राकृतिक पर्यावरण पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, ताकि प्रगति में इसे कोई नुकसान न पहुंचने पाये।

उत्तराखंड सरकार द्वारा परिकल्पित पर्यटन नीति राज्य में पर्यटन से संबंधित नई गतिविधियों के विकास के लिए रोडमैप तैयार करती है। राज्य उद्योग जगत से जुड़े ऐसे निवेशकों के लिए पूंजी सब्सिडी, ब्याज अनुदान, विपणन और संवर्धन, प्रशिक्षण आदि सहित कई प्रोत्साहन दे रहा है, जो उत्तराखंड के पर्यटन विकास में निवेश करना चाहते हैं। इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसमें आतिथ्य सेवाओं से लेकर अन्य पर्यटन सेवाएं जैसे एडवेंचर पार्क, इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवाएं आदि शामिल हैं।

उत्तराखंड को अपनी अद्वितीय पारिस्थितिक स्थिति का लाभ मिलता रहा है। हिमालय दुनिया की सबसे सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है,जहां समय के साथ-साथ भौगोलिक परिवर्तन

> राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं, जिनमें एडवेंचर गेम, योग और स्वास्थ्य व सीमावर्ती गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने से लेकर मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से राज्य के छिपे हुए रत्नों की यात्रा को बढ़ावा देना आदि शामिल है

होते रहते हैं। पर्यटन नीति 2023-2030 पर्यावरण के अनुकूल स्थायी पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिशानिर्देश देती है। हाल ही में सरकार ने राज्य में 1-5 करोड़ रुपये के निवेश के लिए निवेश प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं। राज्य का लक्ष्य यहां के भूमि मालिकों के लिए उद्यमिता विकसित करना है। नीति की एक और विशेषता यह है कि निवेशकों को अपने उद्यम में कम से कम 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। इसमें भौगोलिक स्थिति के आधार पर पूंजी सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी सहित कई प्रोत्साहन शामिल हैं।

बेहतर कनेक्टिविटी से अर्थव्यवस्था को मिल रहा बल

रेलमार्ग, राजमार्ग और हवाई मार्ग के क्षेत्र में प्रगति कर उत्तराखंड न सिर्फ परिवहन में सुधार कर रहा है, बल्कि यात्रा को आसान बना रहा है। इस तरह से पर्यटन और वित्तीय अवसरों को भी विस्तार मिल रहा है

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना : ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर की ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन राज्य के परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मील का पत्थर है। 2010-11 में रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित यह उपक्रम तीर्थ स्थलों तक आरामदायक पहुंच को सक्षम बनाने, नए व्यापारिक केंद्रों को जोड़ने और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक ठोस पहल है। देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली से होकर गुजरने वाली यह रेलवे लाइन देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगी।

सुरंग निर्माण में रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां : ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना में एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि मात्र 44.7 महीनों में 25 किलोमीटर न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से खुदाई पूरी कर ली गई है, जिससे देश में सबसे तेज गति से सुरंग बनाने का नया रिकॉर्ड बना है। परियोजना ने 23 अगस्त, 2022 को एक ही दिन में 107.9 मीटर सुरंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे : इसके मई 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। 210 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा की अवधि को मौजूदा 5 घंटे से घटाकर सिर्फ 2.5 घंटे कर देगा। यह छह लेन वाला राजमार्ग है, जिसे आठ लेन तक विस्तारित किया जाना है। यह न केवल यातायात की भीड़ को कम करेगा, बल्कि यह आवासीय और रिटेल विस्तार को भी बढ़ावा देगा। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का एक अनोखा पक्ष इसका वाइल्ड लाइफ कोरिडोर है, जो स्थानीय जीवों को बचाने के लिए विकसित किया गया है और यह 12 किमी लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर है।

हवाई संपर्क : उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत शुरू की गई देहरादून-पिथौरागढ़ उड़ान सेवा ने दोनों शहरों के बीच यात्रा की अवधि को सड़क मार्ग से 12-15 घंटे से घटाकर हवाई मार्ग से केवल 60 मिनट तक कर दिया है। इस सेवा से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के बीच संपर्क में सुधार हुआ है, जिससे पर्यटन और वित्तीय गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। मार्च 2024 में शुरू की गई देहरादून से अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए नई उड़ानों ने राज्य के हवाई नेटवर्क को विस्तार दिया है।

PIC: DIPR, UTTARAKHAND GOVERNMENT

रेलवे नेटवर्क को बढ़ावा देना : टनकपुर-देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी बेहतरी को दर्शाता है। विभिन्न स्टेशनों को जोड़ने से यह स्थानीय लोगों और यात्रियों दोनों के लिए सुगम यात्रा की सुविधा प्रदान कर रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड में छह स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। राज्य में रेलवे बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को भी सुधारा जा रहा है। देहरादून और आनंद विहार व लखनऊ जैसे अन्य प्रमुख शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेनों की शुरूआत उत्तराखंड के रेल नेटवर्क को अपडेट करने के प्रतिबद्धता को दर्शात है। देहरादून से अयोध्या, वाराणसी और काठगोदाम व देहरादून के बीच दिन में सेवा सहित अतिरिक्त वंदे भारत मार्गों की योजना से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे यात्रा अधिक कुशल और आरामदायक होगी।

ऋषिकेश: लाखों लोगों को प्रेरित कर रही योग राजधानी

हिमालय की तलहटी में स्थित ऋषिकेश लंबे समय से दुनिया की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। हर साल दुनिया भर से हजारों योग उत्साही, आध्यात्मिक साधक और वेलनेस ट्रैवेलर्स अपने योगाभ्यास को बेहतर करने, प्रसिद्ध योग कार्यक्रमों में भाग और योग प्रशिक्षण लेने के लिए इस शांत शहर में आते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश को योग स्थल के रूप में वैश्विक मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने खुद उत्तराखंड में कई बार योग का अभ्यास किया है, जिससे स्वस्थ जीवनशैली प्राप्त करने के महत्व को बल मिला है। उनका विजन ऋषिकेश को न केवल राष्ट्रीय बल्कि योग और वेलनेस टूरिज्म का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ऋषिकेश को योग और आध्यात्मिक कायाकल्प के केंद्र के रूप में सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। दुनिया भर के योग चिकित्सकों के लिए शहर की अपील को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित कई पहल की गई हैं।

हर साल की तरह उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 1 से 7 मार्च तक ऋषिकेश में होगा। इस बहुप्रतीक्षित

कार्यक्रम में प्रसिद्ध योग गुरु, योग साधक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक साथ आएंगे, जो योग की प्राचीन कला को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राज्य के समर्पण को प्रदर्शित करेंगे। ऐसी पहलों के माध्यम से ऋषिकेश योग और आध्यात्मिक उपचार के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी विरासत को संजाए है।

#ExploreUttarakhand

@DIPR_UK

ADVERTORIAL

उत्तराखण्ड शासन

देवभूमि रजत उत्सव

3 साल
सेवा, सुशासन एवं विकास के

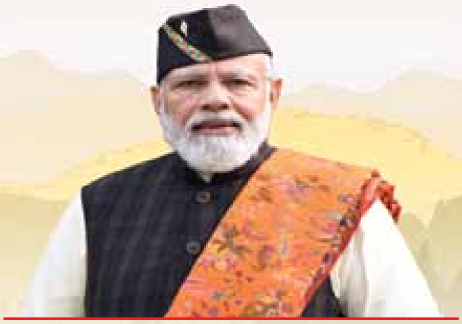

"21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा।"

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

"माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक कहा है। हम प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरुप राज्य को हर क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिये विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं।"

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

संकल्प नये उत्तराखण्ड का

विकसित भारत - सशक्त उत्तराखण्ड

पर्यटन

उत्तराखण्ड के जखोल, सूपी, हर्षिल और गुंजी गांवों को भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में पुरस्कृत किया गया।

वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत सीमांत के 51 गांवों का चयन कर किया जा रहा सुनियोजित विकास।

कुशल प्रबंधन से चारधाम यात्रा पर रिकॉर्ड संख्या में आए श्रद्धालु।

राज्य में पहली बार शीतकालीन यात्रा का हुआ शुभारंभ।

मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अन्तर्गत 48 मन्दिरों तथा अन्य धार्मिक स्थलों को सर्किट के रूप में जोड़ने का कार्य गतिमान।

महासू मन्दिर, हनोल के मास्टर प्लान को दी गई मंजूरी।

कनेक्टिविटी

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा केवल 2.5 घंटे में पूरी होगी।

गौरीकुण्ड से केदारनाथ एवं गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब तक रोपवे निर्माण कार्य को मिली केंद्र सरकार से स्वीकृति। पूर्णागिरी मंदिर रोपवे, काठगोदाम से हनुमानगढ़ी के बीच रोपवे के निर्माण कार्य हेतु प्रक्रिया शुरू।

उड़ान योजना के तहत शुरू की गई देहरादून पिथौरागढ़ उड़ान सेवा ने दोनों शहरों के बीच यात्रा की अवधि को सड़क मार्ग से 12-15 घंटे से घटाकर केवल 60 मिनट कर दिया है।

ऋषिकेश - कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना गांवों को शहरो से जोड़ने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।

₹10,000 करोड़ की भारतमाला परियोजना को सीमा क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए स्वीकृत किया गया।

2030 तक उत्तराखण्ड के सभी गांव सड़क से जुड़ेंगे।

युवा-शिक्षा, रोजगार, सौर स्वरोजगार

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजनाः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, सोलर प्लांट स्थापित करने पर 50% तक सब्सिडी

पिछले 3 वर्षों में लगभग 20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की हुई शुरूआत।

राज्य में पिछले एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4 प्रतिशत की कमी।

उद्योग एवं निवेश

एमएसएमई नीतिः नए औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन

ऊधमसिंह नगर के खुरपिया फॉर्म में भारत सरकार द्वारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्वीकृत।

इन्वेस्टर्स समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू, 30 निवेश अनुकूल नई नीतियां, लगभग 85 हजार करोड़ की ग्राउंडिंग पर कार्य गतिमान।

महिला सशक्तिकरण

हाउस ऑफ हिमालयाज, उत्तराखण्ड महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार जैविक और प्राकृतिक उत्पादों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध

राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण

लखपति दीदी योजनाः महिला स्वयं सहायता समूहों को `5लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण

को-ऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण

मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत राज्य के करीब पौने दो लाख गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त रिफिल।

बड़े निर्णय-बड़े प्रभाव

समान नागरिक संहिता, सशक्त भू-कानून, राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण, सख्त धर्मान्तरण विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, दंगों में सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून

बड़े आयोजन

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 2023: उत्तराखण्ड को लक्ष्य से अधिक 3.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

इन्वेस्टर्स समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू, 30 निवेश अनुकूल नई नीतियां, लगभग 85 हजार करोड़ की ग्राउंडिंग पर कार्य गतिमान।

जी-20 सम्मेलन की बैठकें: जी-20 सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठकों का उत्तराखण्ड में सफल आयोजन।

38वें राष्ट्रीय खेल: देवभूमि को रजत जंयती वर्ष के अवसर पर 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर एवं सफल आयोजन।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन: विभिन्न देशों में रहते हुए व्यापार व अन्य क्षेत्रों में नाम कमाने वाले प्रवासी उत्तराखण्डियों को अपने साथ जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन।

विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो: दिसंबर 2024, देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रैंकिंग में उत्तराखण्ड देश में प्रथम स्थान पर

- समान नागरिक संहिता: सबका साथ सबका विकास
- सख्त धर्मान्तरण विरोधी कानून: जबरन धर्मान्तरण पर रोक
- रेल, रोड, रोपवे और एयर कनेक्टिविटी का विस्तार

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी | www.uttarainformation.gov.in uttarakhandDIPR DIPR_UK uttarakhand DIPR

उत्तराखण्ड शासन

देवभूमि रजत उत्सव

सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता 2025

Explore Uttarakhand Beyond Frames

उत्तराखण्ड राज्य की संस्कृति के प्रचार-प्रसार एवं बारहमासी पर्यटन को बढ़ावा देने, राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित किए जाने हेतु उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आयोजन हेतु मुख्यतः निम्न 8 विषयों के तहत दो श्रेणी (कैटेगरी) 01 मिनट की रील और 05 मिनट की शॉर्ट फिल्मों को शामिल किया गया है, प्रत्येक श्रेणी में एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कृत किया जाएगा।

प्रतियोगिता के विषय (श्रेणी-रील एवं शॉर्ट फिल्म)

- उत्तराखण्ड के पारंपरिक खानपान
- उत्तराखण्ड के होमस्टे
- उत्तराखण्ड के वेडिंग डेस्टिनेशन
- उत्तराखण्ड के बारहमासी पर्यटन
- उत्तराखण्ड के पौराणिक मंदिर एवं तीर्थाटन (अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध)
- उत्तराखण्ड के साहसिक पर्यटन स्थल (अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध)
- उत्तराखण्ड के आयुष एवं वेलनेस
- उत्तराखण्ड के अनछुए मनोरम पर्यटन स्थल

आवेदन प्रारम्भ 1 अप्रैल, 2025 | **अंतिम तिथि 23 अप्रैल, 2025**

पंजीकरण के लिए

लॉग इन करें
https://itda.uk.gov.in/content-competition

या

स्कैन करें

प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित श्रेणियों में चयनित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को ₹5-5 लाख का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

प्रतियोगिता के आवेदन हेतु आवेदक के व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर निम्न में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम-फॉलोवर्स-सब्सक्राइबर्स होने आवश्यक हैं, जिनके स्क्रीनशॉट आवेदक द्वारा आवेदन करते समय पर संलग्न किए जाने अनिवार्य होंगे-

- फेसबुक न्यूनतम 10,000 फॉलोवर
- एक्स न्यूनतम 5,000 फॉलोवर
- यूट्यूब न्यूनतम 5,000 सब्सक्राइबर
- इंस्टाग्राम न्यूनतम 10,000 फॉलोवर

पर्यटन के अनदेखे रंग, देखिए उत्तराखण्ड

एडवेंचर टूरिज्म

पर्यटन के क्षेत्र में देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाला उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ-साथ साहसिक पर्यटन गतिविधियों का गढ़ है। धार्मिक पर्यटन के साथ ही राज्य सरकार ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की है। राज्य में आने वाले पर्यटक ऋषिकेश में राफ्टिंग के साथ ही बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों के जरिए साहसिक रोमांच का आनंद उठा सकते हैं। वहीं पहाड़ों की गोद में बसी टिहरी झील अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों का मन मोह लेती है। पर्यटक इस झील में फ्लोटिंग हाउस, शिकारा बोट और क्रूज, नौका विहार, जेट स्पीड बोट सवारी, वाटर स्कीइंग, जॉर्बिंग, बनाना बोट सवारी, बैंडवैगन बोट सवारी, हॉट एयर बैलून सवारी और पैराग्लाइडिंग जैसी अनेकों गतिविधियों का आनंद उठा रहे हैं।

पैराग्लाइडिंग

पर्यटन का केंद्र कहे जाने वाले उत्तराखण्ड में तीर्थाटन के साथ ही साहसिक पर्यटन गतिविधियां भी देश-विदेश के सैलानियों को आकर्षित कर रही हैं। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से एयर और वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे व्यापक स्तर पर उत्तराखण्ड के साहसिक पर्यटन को पहचान मिलती दिख रही है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन के साथ रोजगार सृजन की दिशा में भी प्रदेश आगे बढ़ रहा है। चारधाम समेत तमाम मठ-मंदिरों की आध्यात्मिक शक्तियों के आगे नतमस्तक विश्व अब उत्तराखण्ड में पर्यटन गतिविधियों के लिए भी खिंचा आ रहा है।

ट्रेकिंग

उत्तराखण्ड ऐसे पहाड़ी इलाकों से भरा हुआ है, जो राज्य को ट्रेकिंग के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थलों में से एक बनाता है। आप यहां अपनी शारीरिक फिटनेस का परीक्षण कर सकते हैं। उत्तराखण्ड अपनी पहाड़ियों में स्थित पगडंडियों और अनछुई भव्यता के कारण यात्रियों का पसंदीदा ट्रेकिंग गंतव्य रहा है। साहसिक व उत्साही लोगों के लिए उत्तराखण्ड ट्रेकिंग के माध्यम से कुछ नया खोजने के लिए अनंत स्थान प्रदान करता है।

पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी-मरतोली-मिलम-रालम ग्लेशियर ट्रेक, बागेश्वर जिले में सुंदरढुंगा-पिंडारी-कफनी ग्लेशियर ट्रेक यहां के सबसे लोकप्रिय ट्रेकिंग मार्गों में से एक है।

स्टारगेज़िंग

स्टारगेज़िंग विज्ञान को जीवन में लाने और हमारी प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता का अनुभव करने का एक जादुई तरीका है। अंतरिक्ष की विशाल छतरी को देखना एक रोमांचकारी अनुभव है जिसका हर कोई आनंद ले सकता है। यदि आप तारों भरे आसमान को निहारना पसंद करते हैं, तो उत्तराखण्ड में इस अनुभव को यादगार पलों में बदलने के लिए अनेकों स्थल हैं।

राज्य के कुछ स्थान जो स्टारगेज़िंग के स्पष्ट दृश्य पेश करते हैं, उनमें औली के पास गोरसन बुग्याल, नैनीताल के पास ज्योलीकोट, उत्तरकाशी के केदारकांठा, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी, मजखाली (रानीखेत के पास एक छोटा-सा गांव), चकराता और चौकोड़ी से स्टारगेज़िंग का भी आनंद लिया जा सकता है।

बंजी जंपिंग

बंजी जंपिंग सिर्फ रस्सी बांधकर ऊंचाई से कूदना नहीं है बल्कि यह एक साहस की छलांग से भी कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसी कूद है, जो आपके दिल से डर को हमेशा के लिए दूर कर देती है और डर मुकाबला करने का साहस पैदा करती है। राज्य में पहाड़ियों से घिरी प्रकृति की गोद से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। उत्तराखण्ड के ऋषिकेश में देश के सबसे ऊंचे बंजी प्लेटफॉर्म में से एक है, जो करीब 83 मीटर (करीब 272 फीट) ऊंचा है।

उत्तराखण्ड होमस्टे

घर जैसा अहसास, उत्तराखण्ड होमस्टे के साथ

ट्रेकिंग रूट पर भी होम स्टे

पर्यटकों को एक और अनोखा अनुभव देने के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने ट्रेकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे योजना शुरू की है। इस अभिनव प्रयास से पर्यटकों को ट्रेकिंग मार्गों पर घर जैसी बेहतर सुविधा और सुरक्षा का अहसास मिला है। साथ ही स्थानीय व्यक्तियों को स्वरोजगार के जरिए तरक्की की सौगात मिली है। ट्रेकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और रूद्रप्रयाग में 15 ट्रेकिंग ट्रक्शन सेंटर अधिसूचित किए गए हैं। यानी कुल 6 जिलों में 87 गांव अधिसूचित किए गए हैं। अब तक लगभग 215 लाभार्थियों का चयन किया गया है। ट्रेकिंग ट्रक्शन सेंटर के 2 किमी के दायरे में आने वाले गांवों में होम स्टे बनाने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी

www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR

डेस्टिनेशन उत्तराखंड

सतत विकास को प्रोत्साहन

हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। हम जो भी कदम उठा रहे हैं, वह इसी लक्ष्य के अनुरूप है। पिछले तीन वर्षों में हमने सेवा, सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। हर क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम मजबूत, समृद्ध और सक्षम उत्तराखंड के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

–पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई

PICS: DIPR UTTARAKHAND

सफलता के तीन साल: निरंतर विकास और समृद्धि पथ पर तीव्र गति से अग्रसर उत्तराखंड

सकारात्मक बदलाव के तीन वर्षों का उत्सव मनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन, कनेक्टिविटी, शिक्षा, उद्योग और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही, समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य ने नए मानक स्थापित किए हैं।

उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक भव्यता, आध्यात्मिक विरासत और समृद्ध संस्कृति के कारण विश्व का ध्यान आकर्षित करता रहा है। देवभूमि के रूप में विख्यात उत्तराखंड देश के दिल में एक अद्वितीय स्थान रखता है। राज्य चार धाम (केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री) सहित कई अन्य प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों के लिए भी जाना जाता है। अपनी परंपराओं, इतिहास और जैव विविधता को समेटे हुए उत्तराखंड विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता को विस्तार दिया है। राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक अपने तीन साल पूरे करने के साथ ही सतत विकास, वित्तीय विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव लाए हैं।

उत्तराखंड की प्रगति को लेकर धामी सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि वह ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं, जो न केवल पर्यटन और आध्यात्मिकता का केंद्र हो, बल्कि सुशासन, नवाचार और समावेशिता के नए मानक गढ़े। राज्य सरकार सुदृढ़ नीतियों को लागू करके उद्यमशीलता, बुनियादी ढांचा, निवासियों को बेहतर जीवन और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम कर रही है। साथ ही, पर्यटन, कनेक्टिविटी, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में भी विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसे में उत्तराखंड की प्रगति अन्य राज्यों के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में धामी सरकार ने कई बेमिसाल उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी यह उपलब्धियां विकास के दृढ़ संकल्प और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है। उत्तराखंड सरकार ने जहां एक ओर बुनियादी सुविधाओं पर ज्यादा बल दिया है, वहीं दूसरी भविष्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर भी पूरजोर प्रयास किए गए हैं, जो समग्र विकास को दर्शाते हैं। इनमें पर्यटन, कनेक्टिविटी, युवा कल्याण, निवेश और महिलाओं को समानता जैसे विषयों पर विशेष बल दिया गया है।

तीन साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने की विकास योजनाओं की घोषणा

धामी सरकार की इस यात्रा में सेवा, विकास और सुशासन की छवि साफ झलकती है, जोकि सरकार के अडिग समर्पण पर बल देती है, जो उत्तराखंड की उन्नति और समृद्धि का मजबूत आधार तैयार कर रही है।

धामी सरकार के तीन साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने की रोजगार नीतियों और युवा कल्याण की घोषणा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेमिसाल तीन साल पूरे होने पर देहरादून के परेड ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रोजगार और युवा कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों की घोषणा की। मुख्य घोषणाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण, उपनल और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थानीय ठेकेदारों को 10 करोड़ रुपये तक की सरकारी परियोजनाओं का विशेष आबंटन शामिल है।

हरित खेलों से जुड़ी अभिनव पहल

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में न केवल शानदार एथलेटिक प्रदर्शन किया, बल्कि हरित खेलों की थीम से जुड़ी अभिनव पहलों के माध्यम से भी धूम मचाई। स्थायी प्रथाओं से लेकर स्थानीय संस्कृति और महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने तक किए जा रहे राज्य के प्रयासों ने राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन पहलों की प्रशंसा की है।

राज्य ने पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाया है। महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। साथ ही, अपनी समृद्ध स्थानीय संस्कृति का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, योग और मल्लखंब जैसे पारंपरिक खेलों को पहली बार पदकों की गिनती में शामिल किया गया है।

21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड, इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा।

–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

> उत्तराखंड सरकार ने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह यात्रा राज्य की उपलब्धियों का सम्मान करने का उपयुक्त समय है

युवा शिक्षा और रोजगार से आने वाली पीढ़ियों को बना रहे सशक्त

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में युवाओं को सशक्त बनाने और कुशल कार्यबल को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि यहां के युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराए जाएं। राज्य सरकार इसमें प्रदेश की प्रगति को देखते हुए इस दिशा में कार्य कर रही है।

सरकारी नौकरियां: पिछले तीन वर्षों में लगभग 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। इससे राज्य में बेरोजगारी दर में 4% की कमी आई है।

सौर स्वरोजगार योजना: मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 133 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्रों के लिए 750 आबंटन पत्र आबंटित किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं सृजित हो सकेंगी।

नियुक्ति पत्र वितरित करते सीएम धामी

उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई हैं। इसके तहत 100 मेधावी पीएचडी छात्रों के लिए 5,000 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति को मंजूरी दी गई है।

वर्चुअल क्लासेज: 500 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेज चलाई जा रही हैं, जिससे सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिल पा रही है।

तीर्थयात्रा और ईको-टूरिज्म को मिल रहा प्रोत्साहन

देवभूमि के रूप में विख्यात उत्तराखंड हमेशा से तीर्थयात्रा और पर्यटन का केंद्र रहा है। राज्य सरकार विभिन्न प्रयासों से यहां पर सुविधाओं को विस्तार दे रही है

पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने पर्यटन और तीर्थयात्रा को प्रोत्साहित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं, जिससे जहां एक ओर सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, वहीं, यह राज्य की अर्थव्यवस्था का ठोस आधार भी बन गया है।

चारधाम यात्रा और शीतकालीन यात्रा: धामी सरकार ने चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया। विशिष्ट पहल के अंतर्गत पहली बार राज्य में शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई, जिससे तीर्थयात्रियों को ठंड के महीनों में भी पवित्र तीर्थस्थलों के दर्शन करने का अनुभव मिला।

सीएम धामी कॉर्बेट पार्क के दौरे पर

मानसखंड मंदिर माला मिशन: मानसखंड मंदिर माला मिशन कुमाऊं क्षेत्र के 48 मंदिरों और गुरुद्वारों को जोड़ने वाला एक सर्किट है, जहां पर विकास कार्य चल रहे हैं। हनोल में महासू मंदिर के लिए मास्टर प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे धार्मिक पर्यटन में भी सुधार होगा। यह प्रयास उत्तराखंड को नई पहचान देगा।

उत्तरकाशी के मुखवा की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री धामी व अन्य

PICS: DIPR UTTARAKHAND

सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव: जखोल, सूपी, हर्षिल और गुंजी गांवों को केंद्र सरकार ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में मान्यता दी है, जो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के समर्पण को दर्शाता है।

वेलनेस और ईको टूरिज्म: राज्य में पर्यटकों की बड़ी संख्या को आकर्षित करने के लिए वेलनेस टूरिज्म, होमस्टे, इको-टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन को विकसित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी का हर्षिल घाटी दौराः उत्तराखंड के विकास को बढ़ावा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर्षिल घाटी और गंगा नदी के मायके मुखवा में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बात चाहे वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन जी-20 बैठक की हो या उत्तराखंड में यूसीसी कानून के कार्यान्वयन की, राज्य के हर प्रयास में प्रधानमंत्री जी का समर्थन मिलता रहा है। इससे राज्य के विकास को गति मिली है। उन्होंने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं के लिए भी आभार व्यक्त किया, जिनकी लागत क्रमशः 4,081 और 2,730 करोड़ रुपये है। उन्होंने तीर्थयात्रियों की पहुंच और धार्मिक पर्यटन बढ़ाने में उनकी भूमिका पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से शीतकालीन पर्यटन, एडवेंचर गतिविधियों, नंदा राज जात यात्रा और कुंभ मेले जैसे प्रमुख धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा मिलेगा।

बेहतर होती कनेक्टिविटी: घट रही दूरियों के साथ सुविधाओं को मिल रहा विस्तार

राज्य में चल रहीं कई बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं ने न केवल सुगमता में सुधार किया है, बल्कि आर्थिक विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है

दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड से बेहतर होगी कनेक्टिविटी

PICS: DIPR UTTARAKHAND

उत्तराखंड सरकार के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाना सबसे अहम प्राथमिकताओं में शामिल रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंच बन सके और शहरों से उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे।

रोपवे परियोजनाएं

केंद्र सरकार ने गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अलावा पूर्णागिरी मंदिर रोपवे और काठगोदाम से हनुमानगढ़ी रोपवे परियोजनाएं भी निर्माणाधीन हैं।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे

दिल्ली और देहरादून के बीच एलिवेटेड रोड पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। निर्माण पूरा हो जाने के बाद दोनों शहरों के बीच लगने वाला यात्रा का समय घटकर सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएगा।

हवाई कनेक्टिविटी

पिथौरागढ़-पंतनगर, पिथौरागढ़-दिल्ली और देहरादून-पिथौरागढ़ मार्गों पर नियमित उड़ानें शुरू की गई हैं, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो गया है। उड़ान योजना के तहत हेली सेवाओं ने नैनीताल, बागेश्वर और मुनस्यारी जैसे पहाड़ी जिलों को जोड़ा है।

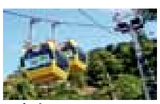

रोपवे

रेलवे परियोजनाएं

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है और टनकपुर-बागेश्वर रेल मार्ग सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है, जिससे दूरदराज के इलाकों तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

महत्वपूर्ण आयोजन: वैश्विक मंच पर चमका उत्तराखंड

राज्य ने अपनी क्षमता और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की सफलतापूर्वक मेजबानी की है।

38वें राष्ट्रीय खेल: उत्तराखंड ने 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, जो राज्य के रजत जयंती वर्ष का प्रतीक है।

जी-20 शिखर सम्मेलन बैठकें: राज्य ने जी-20 शिखर सम्मेलन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठकों की सफलतापूर्वक मेजबानी की।

विश्व आयुर्वेद कांग्रेस: देहरादून में आयोजित विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन: इस सम्मेलन ने विदेशों में रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों को उनकी जड़ों से जोड़ा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिला।

इन अवसरों ने न केवल पर्यटन को बढ़ावा दिया है, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और वित्तीय संभावनाओं को भी बल दिया है।

महिला सशक्तिकरण: समानता के साथ अवसरों का सृजन कर रही सरकार

उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और राज्य के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण: सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% और सहकारी प्रबंध समितियों में 33% आरक्षण लागू किया गया है।

लखपति दीदी योजना: लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।

मुफ्त गैस रिफिल योजना: मुख्यमंत्री अंत्योदय मुफ्त गैस रिफिल योजना के तहत लगभग 1.75 लाख जरूरतमंद परिवारों को सालाना 3 सिलेंडर की मुफ्त रिफिल मिल रही है।

स्थानीय कारीगरों का काम देखते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

ड्रोन सखी पहल: महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे प्रौद्योगिकी और कृषि में नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं।

इन प्रयासों से न केवल महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, बल्कि राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान दिया जा रहा है।

उद्योग एवं निवेश: पारिस्थितिकी विकास को मिल रही गति

उत्तराखंड सरकार ने निवेशकों और उद्यमियों के लिए राज्य को पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए सक्रिय पहल की है। इसके अंतर्गत अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतियों और पहलों को लागू किया है

उत्तराखंड सरकार ने निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों को लागू किया है, जिससे राज्य कारोबार और नवाचार का केंद्र बन गया है।

वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन: वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में 3.56 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 75,000 करोड़ रुपये के निवेश पहले ही शुरू हो चुके हैं।

स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप: केंद्र सरकार ने उधम सिंह नगर के खुरपिया फार्म में एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप के निर्माण को मंजूरी दी।

एमएसएमई नीति: सरकार ने नए औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ उद्यमिता और वित्तीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई नीति पेश की।

देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में उत्तराखंड सरकार के ब्रांड 'हाउस ऑफ हिमालयाज' का शुभारंभ करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

हाउस ऑफ हिमालयाज: राज्य ने जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की स्थापना की, जिसमें 27 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुए।

इंवेस्टर्स समिट

उल्लेखनीय उपलब्धियां : दिख रहे सकारात्मक बदलाव

उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे राज्य विकास के आदर्श मॉडल के रूप में बदल गया है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक: नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी सूचकांक में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है।

एम्स सैटेलाइट सेंटर: उधम सिंह नगर में एम्स सैटेलाइट सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

एकता मॉल और स्मार्ट टाउनशिप: केंद्र सरकार ने एकता मॉल और स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप के निर्माण के लिए 136 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

डिजिटल बदलाव: पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करते हुए अपुणि सरकार पोर्टल के माध्यम से 866 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है।

ये उपलब्धियां समग्र विकास और सुशासन के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाती हैं।

उत्तराखंड सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सेवा, विकास और सुशासन में नए मानक स्थापित किए हैं। पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से लेकर महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने तक, राज्य ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार द्वारा लिए गए सक्रिय निर्णयों, महत्वपूर्ण घटनाओं और परिवर्तनकारी प्रयासों ने उत्तराखंड को भारत में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है। जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की सरकार की इच्छाशक्ति निरंतर बनी हुई है। भविष्य के दृष्टिकोण और समावेशी विकास की प्रतिज्ञा के साथ उत्तराखंड आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है।

#ExploreUttarakhand

Text by Taresh Dutta

CONSUMER CONNECT INITIATIVE

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

उत्तराखण्ड शासन

देवभूमि रजत उत्सव
9 नवंबर 2024-25 | उत्तराखण्ड

प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में

उत्तराखण्ड

विकास के नये अध्याय

की ओर अग्रसर

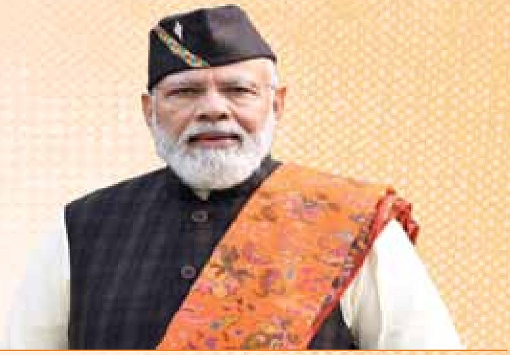

" 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हरसंभव प्रयास।
आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। "

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

" प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखण्ड समय के साथ परिवर्तनकारी विकास का साक्षी बन रहा है। अत्याधुनिक रोपवे परियोजनाओं के साथ-साथ रेलवे, सड़क और हवाई संपर्क की दिशा में प्रगति हो रही है। इससे उत्तराखण्ड में यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव न केवल पर्यावरण अनुकूल हैं, बल्कि कुशल परिवहन भी सुनिश्चित करते हैं। ये राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। आध्यात्मिक, रोमांचक और सांस्कृतिक पर्यटन के प्रभाव के चलते यह दुनिया भर के आगंतुकों के लिए एक पंसदीदा गंतव्य बन रहा है। हम सतत विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक समृद्ध कल की ओर देख रहे हैं। "

जय हिन्द-जय उत्तराखण्ड

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

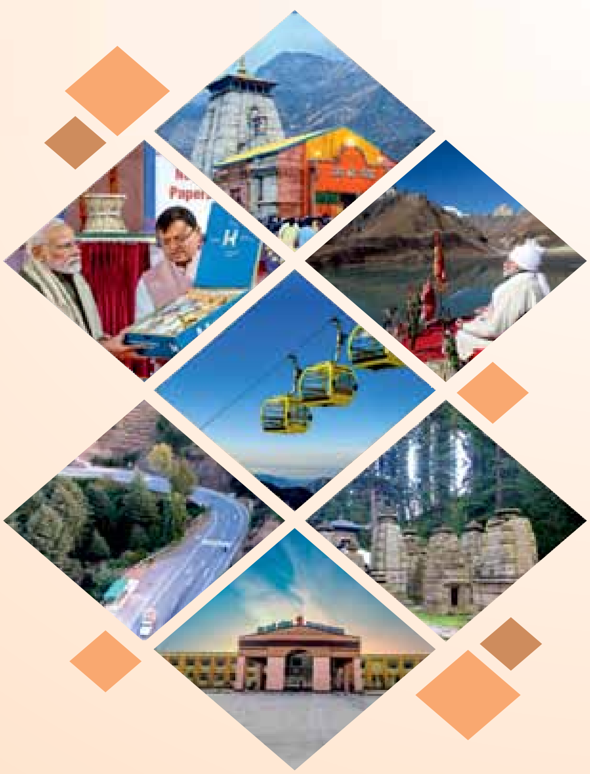

विकसित भारत, सशक्त उत्तराखण्ड

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट - 2023 के दौरान राज्य सरकार के साथ कुल 3.5 लाख करोड़ रुपये के हुए निवेश समझौते। जिसमें 81 हजार करोड़ के समझौते की ग्राउण्डिंग।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में श्री केदारनाथ धाम का हुआ भव्य एवं दिव्य पुनर्निर्माण कार्य। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य गतिमान।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आदि कैलाश और जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद मानसखंड यात्रा को मिली नई पहचान।
- चार धामों की कनेक्टिविटी के लिए ऑल वेदर रोड का हुआ निर्माण। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन का निर्माण कार्य तथा टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन सर्वे का कार्य गतिमान।
- नैनीताल जिले की बहुद्देशीय जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत मिली मंजूरी।
- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम की लखवाड़ परियोजना को मिली मंजूरी।
- उत्तराखण्ड को दो वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात। देहरादून से दिल्ली एवं देहरादून से लखनऊ का सफ़र हुआ आसान।
- दिल्ली - देहरादून के बीच एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य तेजी से जारी, 2 से 2.5 घंटे में सफर होगा पूरा।
- पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिये पर्वत माला परियोजना को मिली मंजूरी। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब एवं पूर्णागिरी मंदिर तक रोपवे के निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास।
- उधमसिंहनगर के किच्छा क्षेत्र में एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य गतिमान। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखण्ड के सीमांत गावों का हो रहा चहुँमुखी विकास।
- जौलीग्रांट एयरपोर्ट एवं पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु कार्य गतिमान।
- प्रधानमंत्री ने दिया वेड - इन - उत्तराखण्ड का मंत्र। जिसके तहत राज्य सरकार नए वेडिंग डेस्टीनेशन का कर रही निर्माण।

नीति आयोग भारत सरकार की ओर से एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखण्ड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी।

www.uttarainformation.gov.in uttarakhandDIPR DIPR_UK uttarakhand DIPR